शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 292 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 29 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

तृणमूल कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी कलह, शांतनु सेन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद... पेज 2
संविधान निर्माताओं का सपना हुआ साकार यूसीसी समान अधिकारों की... पेज 3
सरकारी जमीन पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, बिहार सरकार ला रही नया... पेज 5
नार्वे चेस 2026 : तीसरे दौर में बड़ा उलटफेर प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया पेज 7

अब मेघालय में भी हो रही यूसीसी की तैयारी

सीएम ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे

शिलांग। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पास होने के बाद पूर्वोत्तर में सियासी हलचल तेज हो गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के। सांग्मा ने कहा है कि उनकी सरकार यूसीसी के प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों का गहराई से अध्ययन कर रही है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सांग्मा ने कहा कि पहले यूसीसी को लेकर कई तरह की आशंकाएं थीं क्योंकि कानून के प्रावधान साफ नहीं थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द ने अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग तरह की चिंताएं पैदा की थीं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मेघालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता जनजातीय परंपराओं की सुरक्षा, पारंपरिक कानून और राज्य की मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को बचाना है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार को डर था कि यूसीसी लागू होने से इन परंपराओं में दखल हो सकता है। हालांकि, सांग्मा ने -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई बकरीद

गुवाहाटी/जोरहाट/नलबाड़ी। गुवाहाटी के ईदगाह मैदान से लेकर नलबाड़ी के प्रार्थना मैदान तक, और बारिश से लथपथ जोरहाट से लेकर ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के समुदायों तक, असम ने गुरुवार को भक्ति, गर्मजोशी और शांति के साझा संकल्प के साथ ईद-उल-अधा मनाया। राज्य भर में हजारों श्रद्धालु सुबह-सुबह मस्जिदों में एकत्रित हुए और ईदगाहों के मैदानों को सजाया, नमाज अदा की और समुदायों के बीच सद्भाव के लिए प्रार्थना की। बकरीद या कुर्बानी ईद के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्योहार त्याग और भक्ति की भावना का प्रतीक है, और इस वर्ष इसमें एक अतिरिक्त आयाम जुड़ गया - मुख्यमंत्री की अपील और राज्य -शेष पृष्ठ दो पर

गुरुवार को गुवाहाटी के हातीगांव ईदगाह में ईद-उल-अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। फोटो-दशरथ डेका

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने दी शुभकामनाएं

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज ईद-उल-अजहा के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। ईद-उल-अजहा यानी बकरीद आज देश के अधिकांश हिस्सों में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखा कि ईद-उल-अजहा मनाने वालों को मेरी शुभकामनाएं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। देशभर के साथ-साथ असम में -शेष पृष्ठ दो पर

कोकराझाड़ में फिर से उठी अलग बोड़ोलैंड राज्य की मांग

कोकराझाड़। बोड़ो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन (बोन्सू) की पहल पर असम के कोकराझाड़ जिले के बोड़ोलैंड गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान 28 मई को एक अलग बोड़ोलैंड राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग पर चर्चा फिर से शुरू हुई। इस बैठक में देशभर के छोटे राज्यों की मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें लघु राज्य समन्वय समिति के मुख्य संयोजक संजय थुलुंग, बोन्सू के अध्यक्ष बंजीत मंजिल बसुमतारी, बोड़ोलैंड जनजाति सुरुखा मंच के कार्यकारी अध्यक्ष दाओराव देशरेप नारजरी के साथ-साथ कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनमें ऑल बीटीएडी गांवबुराह -शेष पृष्ठ दो पर

मिया टिप्पणी मामले में दिल्ली की अदालत ने असम सीएम को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका पर हिमंत विश्व शर्मा को नोटिस जारी किया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री के *मिया मुसलमानों* पर *भड़काऊ* टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने विश्व को यह नोटिस तब जारी किया जब वे मजिस्ट्रेट अदालत के 20 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ मंदर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। 26 मई के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका के साथ प्रस्तुत गृह मंत्रालय द्वारा जारी शून्य एफआईआर और ई-एफआईआर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के मद्देनजर, प्रतिवादियों को पुनरीक्षण याचिका -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

जो गलतियां नहीं करता, वह प्राय कुछ नहीं कर पाता।

-ए. जे. फेलप्स

ईडी ने असम में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट पर मारा छापा

13 लाख रुपए नकद और लग्जरी कारें जब्त की

गुवाहाटी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट और उससे प्राप्त *अपराध की आय* के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गुवाहाटी, तिनसुकिया और नई दिल्ली में स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन द्वारा दीपेश बाजोरिया, रोनक बाजोरिया, राजेश जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और असम गेम एंड बेटिंग एक्ट, 1970 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इसके बाद, तिनसुकिया पुलिस स्टेशन द्वारा बिकाश बेरिया, नितिन बेरिया, सुप्रित विश्वस और अन्य के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गईं, जो एक परस्पर जुड़े गिरोह द्वारा चलाए जा रहे इसी तरह के अवैध आईपीएल सट्टेबाजी संचालन से संबंधित थीं। -शेष पृष्ठ दो पर

देशभर से एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा : शाह

अहमदाबाद (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल चुनाव में जो वादे किए थे, उसके अनुसार बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि देशभर से एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री शाह अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को अहमदाबाद के एस.जी. हाइवे स्थित सोला उमियाधाम कैंपस में पाटीदार समाज के युवाओं के लिए नवनिर्मित जे.एस. पटेल कुमार छात्रावास और तपस्वीकुमार पटेल कन्या छात्रावास के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के 80 प्रतिशत भूभाग पर भाजपा का शासन है। हमने पश्चिम बंगाल चुनाव में जो वादे किए थे, उसके अनुसार बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सात दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। हमारी सरकार का संकल्प है कि देशभर से एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार *डेमोग्राफी चेंज कमीशन* की स्थापना कर रही है, जो एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और अवैध जनसंख्या संतुलन को रोकने के लिए नए कानून की दिशा में काम करेगा। गृहमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद करते हुए कहा कि आज वीर सावरकर की जयंती है। वे ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त थे जिन्हें किसी सरकारी सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

उन्नाव में प्रतिबंधित संगठन अल्फा-आई से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

उन्नाव। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (अल्फा-आई) से कथित रूप से जुड़े दो आरोपियों को उन्नाव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपियों -शेष पृष्ठ दो पर

कोलकाता में हटाई जाएगी लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगी लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति को सुरक्षा कारणों से हटाया जाएगा। ईएसपीएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि हवा चलने पर यह मूर्ति हवा में झूलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का फैसला लिया। मेसी की यह विशाल मूर्ति पिछले साल दिसंबर में बनाई गई थी। इसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 -शेष पृष्ठ दो पर

सीबीएसई विवाद के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार : राहुल गांधी

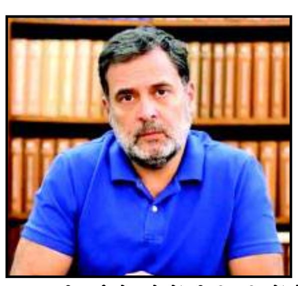

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर विवाद के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मामले की चाहे जांच की गई हो या न की गई हो, दोनों ही स्थितियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। यदि प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों की चिंता होती तो वे मंत्री को बहुत पहले ही पद से हटा देते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के लगातार चुनावी हार की कुंठा वाले बयान पर -शेष पृष्ठ दो पर

कर्नाटक : सिद्धारमैया ने छोड़ा मुख्यमंत्री पद, डीके शिवकुमार होंगे अगले सीएम

बेंगलुरु (हि.स.)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ अपने आवास पर ब्रेकफास्ट के साथ बैठक कीथी। हालांकि यह बैठक एक घंटा देर से शुरू हुई क्योंकि सिद्धारमैया खुद एक घंटे की देरी से अपने आवास में उस जगह पहुंचे, जहां मंत्रियों के लिए ब्रेकफास्ट की टेबल सजी थी। बैठक में शिवकुमार और सिद्धारमैया ने एक-दूसरे को गले लगाकर एकजुटता का संदेश दिया और शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सिद्धारमैया ने अपने सभी साथियों का धन्यवाद दिया। इसके बाद सिद्धारमैया राजभवन पहुंचे। राज्यपाल की -शेष पृष्ठ दो पर

राजस्थान : स्कॉर्पियो में जिंदा जले पूर्व सरपंच, मां-बेटे सहित चार लोग

अजमेर (हि.स.)। अजमेर जिले में गुरुवार तड़के एक स्कॉर्पियो में आग लगने से पूर्व सरपंच मां-बेटे सहित चार लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुई। शुरुआती तौर पर मामला हादसा माना जा रहा था, लेकिन मौके से मिले सुबूतों के बाद पुलिस अब हत्या के एंगल से भी जांच रही है। इस घटना में श्रीरामपुरा निवासी एवं पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी मां एवं पूर्व सरपंच पुसी देवी, पत्नी एवं कांग्रेस समर्थित -शेष पृष्ठ दो पर

भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक : ओम बिरला

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह अपने संवाद, सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों की समृद्ध परंपराओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों को प्रेरित कर रहा है। दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक कक्ष में गुरुवार को केंद्रीय विधान सभा (1924-1930) की कार्यवाही के 89 खंडों और त्रैमासिक पत्रिका *विधान-चेतना* के प्रथम अंक के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जिसमें संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। इस मौक पर दिल्ली के विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापक और शिक्षक मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक शक्ति जागरूक संवाद, -शेष पृष्ठ दो पर

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा

मेरे पूर्वज हिंदू थे..., पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा *झूठा इतिहास*

इस्लामाबाद। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था और इतिहास लेखन पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि देश के बच्चों को *गलत इतिहास* पढ़ाया जा रहा है। उनके बयान ने पाकिस्तान में पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के कई लोग अपनी असली जड़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आधे लोग यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं? ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इतिहास की किताबों से कई महत्वपूर्ण भारतीय शासकों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लगभग मिटा दिया गया। उन्होंने कहा कि -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

तृणमूल कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी कलह, शांतनु सेन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। इसी क्रम में राज्यसभा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ तृणमूल नेता शांतनु सेन ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरजी कर रेप और मर्डर केस समेत कई विवादों को लेकर पार्टी नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा है। पेशे से डॉक्टर और कोलकाता नगर निगम के पार्षद शांतनु सेन ने अपना इस्तीफा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा है। हालांकि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी है। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा कि पार्टी के *वफादार सिपाही* होने के बावजूद अब उनका जमीर उन्हें उन मुद्दों का सार्वजनिक बचाव करने की अनुमति नहीं देता, जिनकी वजह से जनता पार्टी से दूर हो गई। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने टीवी डिबेट और मीडिया मंचों पर पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन अब जनता ने आरजी कर घटना, नौकरी घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार तथा अनैतिक गतिविधियों के कारण पार्टी को नकार दिया है। उन्होंने लिखा कि जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा रेप और मर्डर मामला हाल के वर्षों में तृणमूल के लिए सबसे विवादित मुद्दों में से एक रहा है। पिछले वर्ष ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले को लेकर डॉक्टरों, छात्रों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों में भारी आक्रोश देखा गया था। शांतनु सेन उन चुनिंदा तृणमूल नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने इस मामले में सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। उनके बयानों के कारण पार्टी नेतृत्व असहज हो गया था और उन्हें कुछ समय के लिए *पार्टी विरोधी गतिविधियों* के आरोप में निलंबित भी किया गया था। बाद में उन्हें फिर से प्रवक्ता पद पर बहाल कर दिया गया था। हाल ही में बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नई भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी को बधाई दी थी। इसके अलावा उन्होंने आरजी कर मामले की किसी भी जांच में सहयोग देने की भी सार्वजनिक पेशकश की थी। इस बीच तृणमूल में इस्तीफों और असहमति का सिलसिला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी प्रवक्ता और पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अंतर्गत बरो 12 के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया। वहीं, बारासात से लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के भीतर कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और प्रशासनिक अहंकार जैसे आरोपों ने तृणमूल की चुनावी हार में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से अब तक शांतनु सेन के इस्तीफे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

सिद्धारमैया ने राज्यसभा का ऑफर ठुकराया बोले- राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को राज्यसभा सीट ठुकरा दी और कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभुशंकर को अपना इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद इसकी घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी हाई कमांड ने उन्हें राज्यसभा सीट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे कर्नाटक की राजनीति में बने रहेंगे और विधायक के रूप में अपने शेष दो साल पूरे करेंगे। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा सीट की पेशकश की, लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा, क्योंकि विधायक के रूप में मेरा कार्यकाल अभी दो साल शेष है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बार-बार कहा था कि जब भी पार्टी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आलाकमान ने मुझे दो दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दो बार कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का मौका मिला जिसके लिए मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे को धन्यवाद देता हूं। जब सिद्धरमैया अपना इस्तीफा सौंपने लोकभवन गए तब उनके साथ शिवकुमार एवं अन्य मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी थे। सिद्धरमैया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा सीट की पेशकश की, लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की राजनीति में बना रहूंगा क्योंकि विधायक के रूप में मेरा कार्यकाल अभी दो साल बाकी है। सिद्धरमैया ने कहा कि 550 वादों में से अब तक करीब 300 पूरे किए जा चुके हैं। पांच गारंटी भी लागू की गई हैं। मैं किए गए वादों से कभी पीछे नहीं हटा।

देरगांव में पालतू हाथी के हमले में महावत की मौत

गोलाघाट (हिंस)। असम के गोलाघाट जिले के देरगांव क्षेत्र में एक पालतू हाथी के हमले में एक महावत की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार, देरगांव के मलाई कुमार गांव से रामप्रसाद नामक हाथी को उसका महावत लेकर जा रहा था। उसी रास्ते में शिव मंदिर के पास एक अन्य पालतू हाथी, प्रशांत, पहले से बांस की पत्तियां खा रहा था। इसी दौरान दोनों हाथियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। बताया जाता है कि रामप्रसाद हाथी अचानक आक्रामक हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशांत हाथी का महावत बीच में आया, लेकिन तभी रामप्रसाद ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महावत की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रामप्रसाद हाथी मौके से भाग निकला। बाद में उसके महावत ने पीछा कर उसे बंगालगांव के एक निर्जन इलाके में काबू में किया और जंजीरों से बांध दिया।

भाजपा ने चार राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष

नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। भाजपा ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, हरियाणा में महिला नेता अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने पंजाब में भी संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी ने पंजाब भाजपा की कमान केवल सिंह ढिल्लों को सौंपी है। इसके अलावा त्रिपुरा में विधायक अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नए प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आसाराम के जोधपुर आने की सूचना पर एयरपोर्ट पर उसके समर्थकों की भीड़ लग गई। इस दौरान पुलिस को आसाराम को एयरपोर्ट से निकाल कर गाड़ी में बैठाने के लिए कड़ी मशक्कत हुई। आसाराम जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। वहां से एम्स गया और जांच के बाद सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। बुधवार को उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट की ओर से तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश के बाद आसाराम बुधवार देर शाम ही हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जब आसाराम की अपील खारिज करते हुए उसकी अंतरिम जमानत को रद्द किया, उस समय वह उत्तराखंड के हरिद्वार में था। कोर्ट का फैसला आने और तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी मिलने के बाद आसाराम सड़क मार्ग से हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। आसाराम के समर्थकों का दावा है कि सड़क मार्ग से सफर के चलते तबीयत बिगड़ गई। इसी वजह से दिल्ली एम्स ले जाया गया। सूत्रों की मानें तो आसाराम पक्ष की कोशिश यही थी कि सरेंडर नहीं करना पड़े और उच्चतम न्यायालय में अपील होने तक मेडिकल ग्राउंड का बहाना बना ले लेकिन कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद यह विचार त्याग दिया गया। उच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने इस चर्चित मामले में अपना विस्तृत फैसला सुनाया था।

पृष्ठ एक का शेष

अब मेघालय में भी ...

बताया कि असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू या प्रस्तावित कानूनों को देखने के बाद यह सामने आया है कि जनजातीय समुदायों और उनके पारंपरिक कानूनों को काफी हद तक दायरे से बाहर रखा गया है। जिससे मेघालय सरकार को कुछ हद तक राहत मिली है। सांग्मा ने साफ किया कि मेघालय सरकार यूसीसी को लेकर संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी कानून राज्य की पहचान, पारंपरिक प्रथाओं और जनजातीय अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने दोहराया कि आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

राज्य में शांतिपूर्ण तरीके ...

कानून के प्रावधानों के अनुरूप, गाय की बलि दिए बिना त्योहार मनाने का व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला संकल्प। राज्य की राजधानी में, शहर भर की मस्जिदों में सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की और शांति, समृद्धि और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। आमबारी की बुढ़ा जामे मस्जिद, लाखटोकिया मस्जिद, हातीगांव की राजधनी मस्जिद और काटाबारी मस्जिद सहित प्रमुख मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी हुई थीं। बुढ़ा जामे मस्जिद के महासचिव ने धार्मिक जिम्मेदारी के साथ-साथ नागरिक जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं ईद-उल-अधा के अवसर पर असम के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज कुर्बानी का दिन है और मुझे उम्मीद है कि लोग असम सरकार द्वारा जारी मानक परिचालन निर्देशों (एसओपी) पर ध्यान देंगे और उनका पालन करेंगे। उधर नलबाड़ी में, हजारों लोग नलबाड़ी ईदगाह मैदान और जिले भर के अन्य प्रार्थना स्थलों पर एकत्र हुए और वैश्विक शांति, सद्भाव और सांप्रदायिक एकता के लिए प्रार्थना की। परिवारों और दोस्तों ने गर्मजोशी से ईद की शुभकामनाएं दीं, जो इस त्योहार की विशेषता, एकजुटता की भावना को दर्शाती हैं। सभी को ईद मुबारक। हमारे राज्य में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, और मैं कामना करता हूं कि सभी एकजुट और शांतिपूर्ण रहें ताकि हम सब मिलकर असम को आगे ले जा सकें, हजरत मौलाना कारी मकबीर हुसैन ने कहा। वहीं जोरहाट में, खराब मौसम के बावजूद इस्लामी समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचे, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों ने विशेष प्रार्थनाओं में भाग लिया। मौसम अनुकूल न होने के बावजूद, जोरहाट के लोग नमाज अदा करने के लिए एक साथ आए। जोरहाट ईदगाह कमेटी और जोरहाट के मुस्लिम समुदाय की ओर से, मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं। आशा करता हूं कि हमारे दिन और भी समृद्ध हों और लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता रहे, जोरहाट ईदगाह कमेटी के एक प्रतिनिधि ने कहा। इस वर्ष के उत्सवों ने असम के सार्वजनिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण क्षण को भी प्रतिबिंबित किया। त्योहार से पहले, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य भर की ईद समितियों से आग्रह किया था कि वे उत्सवों में गौ-बलिदान को शामिल न करें, जो असम पशु संरक्षण अधिनियम के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भर की कई ईदगाह समितियों ने अपने समुदायों से औपचारिक अपील जारी की और कथित तौर पर इस वर्ष गाय की बलि से परहेज किया। जोरहाट ईदगाह कमेटी के प्रतिनिधि ने भी इसी भावना को दोहराया। उन्होंने कहा कि सभी ने मुख्यमंत्री की अपील का समर्थन किया। असम हमेशा से एक शांतिपूर्ण राज्य रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। असम में, एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान सर्वोपरि है, धर्म बाद में आता है।

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने ...

भी गुरुवार को पवित्र ईद-उल-जुहा धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के वातावरण में मनाई जा रही है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार, जिल्हज्ज माह की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में विशेष उत्साह देखा गया। ईद को लेकर राज्यभर में उल्लासपूर्ण वातावरण देखने को मिला। मस्जिदों और ईदगाहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पर्व के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। यह पर्व त्याग, समर्पण, प्रेम और मानवता का संदेश देता है तथा समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का कार्य करता है।

कोकराझाड़ में फिर से ...

एसोसिएशन, पूर्व एनडीएफबी सदस्य, पूर्व स्वयंसेवी बल सदस्य और ऑल बोड़ो सीनियर सिटिजन्स फोरम शामिल हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय थुलुंग ने कहा कि छोटे राज्यों की वकालत करने वाले संगठन अलग राज्य की मांग को लेकर अपने आंदोलनों को तेज करने के लिए फिर से एक साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू की जाएगी और जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक आंदोलन फिर से शुरू किए जा सकते हैं। बोन्सू के अध्यक्ष बंजीत मंजिल बसुमतारी ने कहा कि संगठन अलग बोड़ोलैंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। उन्होंने दावा किया कि बोड़ो समुदाय के कुछ वर्ग बीएसी, बीटीसी और बीटीआर व्यवस्थाओं से संबंधित पूर्व समझौतों से अभी भी असंतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि अलग राज्य की मांग जारी रहेगी और भविष्य में और भी मजबूत पहल की जा सकती हैं।

मियां टिप्पणी मामले में दिल्ली...

की सूचना जारी की जाए और उन्हें 15 जुलाई, 2026 तक उचित जवाब दाखिल करने को कहा जाए। अप्रैल में, मंदर ने असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान 27 जनवरी को कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। याचिका के अनुसार, शर्मा ने कथित तौर पर कहा था कि असम में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान *चार से पांच लाख मिया मतदाताओं* को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए *मिया* एक अपमानजनक शब्द है, और गैर-बंगाली भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासी मानते हैं। हाल के वर्षों में, इस समुदाय के कार्यकर्ताओं ने विरोध के प्रतीक के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मंदर के आवेदन में यह भी दावा किया गया कि असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर यह कहकर मिया समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया कि *वे तभी असम छोड़ेंगे जब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा* और यह कि *हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में मतदान न कर सकें।* सेशन कोर्ट के समक्ष, मंदर के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। वकील ने शून्य एफआईआर की अवधारणा पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी किसी भी पुलिस स्टेशन को प्रदान की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी किया गया हो। न्यायालय ने प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया और कहा कि प्रतिवादियों को पुनरीक्षण याचिका की सूचना जारी करें।

ईडी ने असम में ...

जांच से पता चला है कि आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैचों पर एक सुनियोजित, पदानुक्रमित और तकनीकी रूप से सक्षम अवैध सट्टेबाजी और जुए का रैकेट चला रहे थे। दांव लगाने का काम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल फोन द्वारा किया जाता था। यह तलाशी दीपेश बाजोरिया, रोनक बाजोरिया, राजेश जैन, विकास अग्रवाल, सुप्रित विश्वस, बिकाश बेरिया, नितिन बेरिया और दुर्गा प्रसाद बेरिया के आवासीय परिसरों और गुवाहाटी में *रॉयसी* (पूर्व में *प्लेबॉय*) नाम से संचालित एक व्यावसायिक परिसर में की गई। तलाशी के दौरान परिसर से 13 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद कर जब्त की गई है। अपराध से प्राप्त धन से खरीदी गई तीन महंगी गाड़ियां भी जब्त की गईं, जिनमें एक मर्सिडीज-बेंज, एक एमजी हेक्टर और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं।

देशभर से एक-एक ...

देश का बच्चा-बच्चा उन्हें वीर सावरकर के नाम से जानता है। अंग्रेजों ने उन्हें एक ही जीवन में दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। उन्होंने जेल की दीवारों पर अपने खून से कविताएं लिखीं और समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि करीब 4.33 लाख वर्गफुट क्षेत्र में बने इस अत्याधुनिक हॉस्टल में उच्च शिक्षा के लिए आने वाले लगभग 1600 विद्यार्थियों को रहने और भोजन की फाइव स्टार जैसी स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यूपीएससी-जीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्वस्तरीय शैक्षणिक वातावरण भी मिलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल प्रोजेक्ट में 2,16,807 वर्गफुट की बॉयज हॉस्टल और 2,19,807 वर्गफुट की गर्ल्स हॉस्टल बनाई गई है। दोनों मिलाकर कुल 4,33,914 वर्गफुट क्षेत्र में यह विशाल परिसर तैयार किया गया है। ऊंझा कड़वा पाटीदार समाज के उमिया माताजी संस्थान द्वारा तैयार किए गए इस मेगा प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित पाटीदार समाज के वरिष्ठ नेता और कई गणमान्य उपस्थित रहे।

सीबीएसई विवाद के...

पलटवार करते हुए कहा कि प्रधान चाहे उन पर जितना भी हमला करें, इससे 18.5 लाख विद्यार्थियों के लिए जवाब मांगना बंद नहीं करेंगे। राहुल ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली का ठेका *सीओएमपीईटी* कंपनी को दिए जाने पर सवाल उठाया, जो पहले ग्लोबेरेना नाम से विवादों में रही है। उन्होंने पूछा कि यह किसके आदेश पर हुआ, कोई पृष्ठभूमि जांच क्यों नहीं की गई और कंपनी प्रबंधन का सरकार से क्या संबंध है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते कहा था कि राहुल गांधी चुनावी हार की कुंठा के कारण देश की वैज्ञानिक प्रगति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस प्रणाली में हुई किसी भी असुविधा की जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं। सीबीएसई ने इस मामले पर अपना जवाब दिया है जो भारत सरकार की खरीद नीति के अनुरूप है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

कर्नाटक : सिद्धारमैया ने ...

अनुपस्थिति में सिद्धारमैया ने उनके सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके तुरंत बाद कर्नाटक कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उस दिन, आज के दिन, हमेशा के लिए... एकता ही हमारी शक्ति है! जनसेवा ही हमारी शाश्वत प्रतिबद्धता है! बताया गया कि सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट बैठक में अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अगले मुख्यमंत्री के लिए डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव भी कर दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री के नाम पर विधायक दल की मोहर लगनी अभी बाकी है। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है।

राजस्थान : स्कॉर्पियो में जिंदा ...

निवर्तमान जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी तथा भांजी महिमा की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच पुसी देवी के सीने में दर्द की शिकायत थी। इसी कारण रामसिंह चौधरी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सुबह घर से निकले थे। कार में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। गांव से करीब एक किलोमीटर दूर अचानक वाहन में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि आसपास से पानी के टैंकर बुलाकर आग पर काबू पाया गया। हादसे के कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पुलिस जांच के दौरान मृतक सुरज्ञान देवी के गले पर खून के निशान पाए गए। इसके अलावा तलाशी में पुलिस को दो ईंटें और खून के धब्बे भी मिले हैं। इन परिस्थितियों ने घटना को संदिग्ध बना दिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इसे हत्या मानकर भी जांच आगे बढ़ा रही है। रामसिंह चौधरी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय चेहरा माने जाते थे। वे बोराड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके थे और किशनगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके थे। उनकी मां पुसी देवी भी कासीर ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी थीं। वहीं पत्नी सुरज्ञान देवी कांग्रेस से जुड़ी हुई थीं और निवर्तमान जिला परिषद सदस्य थीं। एक ही परिवार के चार लोगों की इस तरह मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक अस्पताल एवं घटनास्थल पर पहुंचे।

भारत का लोकतंत्र पूरी...

तथ्य-परक चर्चा और सक्रिय जनभागीदारी में निहित है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों में लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ करने के लिए भारत की संसदीय विरासत का संरक्षण और गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधान सभा का यह ऐतिहासिक भवन भारत की लोकतांत्रिक चेतना, संसदीय परंपराओं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत प्रतीक तथा गौरवशाली विरासत है। इस परिसर के ऐतिहासिक महत्व को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि इस भवन ने भारत के संसदीय लोकतंत्र के प्रारंभिक कालखंड को देखा है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मंच रहा है, जहां देश के स्वतंत्रता सेनानियों और महान राष्ट्रीय नेताओं ने प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों और स्वशासन के लिए अपनी मुखर संवैधानिक मांगें उठाई थीं। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल के अतुलनीय योगदान का स्मरण करते हुए बिरला ने कहा कि उन्होंने संसदीय शिष्टाचार, निष्पक्षता और अध्यक्ष पद (आसंदी) की गरिमा की एक सुदृढ़ नींव रखी थी। औपनिवेशिक शासन के अत्यंत कठिन समय और भारी दबाव के बावजूद, पटेल ने इस विधायी संस्था की स्वायत्तता और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखा। उनका यह योगदान देश भर के पीठासीन अधिकारियों और विधि निर्माताओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि केवल तर्क, गंभीरता और तथ्यों पर आधारित चर्चा ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सुरक्षित रख सकती है और सार्वजनिक विश्वास को सुदृढ़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति का मूल आधार सदैव चर्चा, आम सहमति और गहन विचार-विमर्श रहा है। अत: संसद और राज्यों की विधान सभाओं को सदैव देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च मंच बने रहना चाहिए। केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही के प्रकाशन को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बिरला ने आशा व्यक्त की कि यह संकलन आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं के एक मार्गदर्शक प्रकाश-स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। त्रैमासिक प्रकाशन विधान-चेतना की सराहना करते हुए बिरला ने इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रयास बताया, जो संसदीय अध्ययनों, विधायी शोध और लोकतांत्रिक जागरूकता को और अधिक सशक्त करेगा। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि यदि विधायी संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। संसद और विधानसभाओं की गरिमा की रक्षा करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का इतिहास स्वयं संसद के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह भवन कभी केंद्रीय विधानसभा के रूप में कार्य करता था और भारत की संसदीय यात्रा में इसका विशेष स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय राजधानी में स्थित होने के कारण दिल्ली विधानसभा की संस्थागत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय कार्यवाहियां किसी भी युग की वास्तविक परिस्थितियों और राष्ट्र की स्थिति को समझने का सबसे प्रामाणिक माध्यम होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति की चेतना को दिल्ली में विशेष स्थान प्राप्त है और इसी कारण यह कार्यक्रम ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। वर्ष 1924 से 1930 तक की विधायी कार्यवाहियों के संकलन और प्रकाशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने केंद्रीय विधानसभा की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण किया। विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि वर्तमान ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण परियोजना के अंतर्गत अब तक 407 बैठकों से संबंधित लगभग 32,000 संसदीय प्रश्नों का संकलन किया जा चुका है तथा दीर्घकालिक लक्ष्य लगभग पांच लाख विधायी अभिलेखों को शोध एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु संरक्षित करना है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि जब प्रामाणिक दस्तावेज और तथ्य जनता के सामने आते हैं, तब इतिहास को कोई विकृत नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षित और विस्मृत पड़े अभिलेखों एवं कार्यवाहियों को अब व्यवस्थित रूप से पुनर्स्थापित कर राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेठ फतेह चंद द्वारा मात्र ग्यारह महीनों में 22 एकड़ भूमि पर निर्मित यह ऐतिहासिक भवन एक अद्वितीय स्थापत्य एवं संस्थागत विरासत है, जो आज भी मजबूती से खड़ा है।

मेरे पूर्वज हिंदू थे...

चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वे हिंदू थे। उनके मुताबिक, पाकिस्तान में ऐसी सोच तैयार की गई जिससे नई पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर हो जाए। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लंबे समय से एक ऐसी मानसिकता विकसित की गई जिसमें लोगों को अपने ही अतीत से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे तथ्यात्मक इतिहास नहीं पढ़ रहे और आज कई युवाओं को यह भी नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कौन थे। यह बयान ऐसे समय आया है जब ख्वाजा आसिफ पहले से ही अमेरिका और इजरायल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा में हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजरायल को मान्यता देने की अपील की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति पर कायम है और जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनता, तब तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद अमेरिका में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमेरिकी रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी भी आधिकारिक तौर पर इजरायल को मान्यता नहीं दी है। यहां तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी साफ लिखा होता है कि यह इजरायल यात्रा के लिए मान्य नहीं है।

उन्नाव में प्रतिबंधित ...

के स्थानीय नेटवर्क और ठिकानों की जांच शुरू कर दी है। उसने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहारनपुर निवासी नूर मोहम्मद और कानपुर निवासी मोहम्मद सुभान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों पिछले करीब छह महीने से उन्नाव के बुधवारी इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे और अपनी पहचान छिपा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि असम पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस और सर्विलांस यूनिट की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर असम पुलिस को सौंप दिया गया। असम पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपी अल्फा-आई के लिए चंदा जुटाने में शामिल थे और उनके खिलाफ तिनसुकिया जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार, जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि उन्नाव में आरोपियों को किसने पनाह दी थी और उनके स्थानीय संपर्क कौन-कौन थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है।

कोलकाता में हटाई ...

जीतने वाले अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रशंसकों ने तैयार कराया था। मूर्ति में मेसी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। यह प्रतिमा उनके भारत दौरे गोट टूर से पहले स्थापित की गई थी। मेसी पिछले साल अपने इंटर मियामी टीम के साथियों के साथ भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली सहित चार शहरों का दौरा किया था। सोमवार को स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से शिकायत की कि तेज हवा चलने पर मूर्ति अस्थिर दिखाई देती है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मूर्ति की संरचनात्मक मजबूती कमजोर हो चुकी है और किसी भी संभावित हादसे से बचने के लिए इसे तुरंत हटाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को तैयार करने में कुल 27 दिन लगे थे।

संविधान निर्माताओं का सपना हुआ साकार यूसीसी समान अधिकारों की नई सुबह : असम भाजपा

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के सदन से पारित होने को भारतीय संविधान निर्माताओं के सपनों की ऐतिहासिक पूर्ति बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व की सराहना की है। पार्टी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के दौरान भारत रत्न बीआर अंबेडकर सहित राष्ट्रनिर्माताओं ने जिस समान कानून व्यवस्था की परिकल्पना की थी, वह अब वास्तविकता में बदल गई है। असम भाजपा के अनुसार संविधान सभा में यह विचार रखा गया था कि संविधान लागू होने के कुछ वर्षों के भीतर देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था स्थापित की जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के चलते विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकार लंबे समय तक प्रभावित होते रहे। भाजपा ने कहा कि भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही *एक देश, एक कानून* के सिद्धांत का पक्षधर रही है। पार्टी के अनुसार विपक्षी दलों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी का लगातार विरोध किया, लेकिन गुजरात और उत्तराखंड की पहल के बाद असम सरकार ने भी इसे लागू करने का संकल्प लिया। हालिया विधानसभा चुनाव में यह असम भाजपा का प्रमुख वादा था, जिसे नई एनडीए सरकार ने विधानसभा के पहले ही सत्र में पूरा कर दिया। पार्टी प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने मीडिया को आज जारी बयान में कहा कि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला कानून साबित होगा। बहुविवाह पर रोक लगने से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जबकि विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण महिलाओं को सामाजिक मान्यता और कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। तलाकशुदा महिलाओं को भरण-पोषण, मुआवजा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी मामलों में भी समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। भाजपा ने कहा कि यूसीसी के तहत लिव-इन संबंधों को भी कानूनी मान्यता मिलेगी और नागरिकों को वसीयत तथा उत्तराधिकार संबंधी मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध होगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जनजातीय समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि उनकी पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके। बयान में कहा गया कि सप्तपदी, आशीर्वाद निकाह, होली यूनियन, वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग विवाह, ब्रह्म विवाह और आनंद कारज जैसी पारंपरिक धार्मिक विवाह पद्धतियों को भी यूसीसी के तहत मान्यता दी गई है। असम भाजपा ने इसे समाज में *सभी के लिए समान कानून* के संवैधानिक आदर्श को वास्तविक रूप से लागू करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है।

महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यूसीसी महत्वपूर्ण कदम : अभाविप

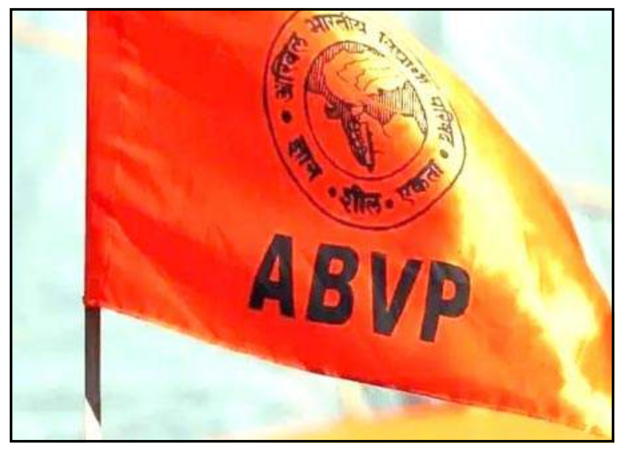

गुवाहाटी (हिंस)। समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से बहुविवाह, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के कारण अनेक महिलाएं मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होती रही हैं, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि 27 मई को असम विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया। इसके साथ ही असम, भारत का तीसरा राज्य तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां यह ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है। असम विधानसभा में पारित इस विधेयक का स्वागत करते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), असम प्रदेश ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। संगठन के राज्य सचिव मानस प्रतिम कलिता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून आवश्यक है। समान नागरिक संहिता समाज में न्याय और सुरक्षा की नींव को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में बहुविवाह, बाल विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप जैसी अपसंस्कृतियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यूसीसी कानून महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा। साथ ही यह कानून महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दो घायल

मोरीगांव (हिंस)। मोरीगांव जिले के जागीरोड इलाके में हुए आज सड़क हादसे में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत दो को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जागीरोड पुलिस ने बताया कि गुरुवार को जागीरोड पुलिस थाना के समीप रेलवे फ्लाईओवर पर हुई स्कूटी और बाइक के बीच में आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक महिला समेत दो लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान धरमतुल अलीसींगा गांव निवासी हिफजूर रहमान के रूप में की गई है। जबकि गंभीर रूप से घायल जागीरोड के नखोला गांव के भास्कर डेका को उन्नत चिकित्सा के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एन्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नाहरलागुन में विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र पंचपदी अधिगम पद्धति प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ

गुवाहाटी (हिंस)। अरुणाचल शिक्षा विकास समिति द्वारा एएसवीएस प्रशिक्षण केंद्र, पाचिन कॉलोनी, नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश में *विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र पंचपदी अधिगम पद्धति प्रशिक्षण कार्यशाला* का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोबिंद चंद्र महंत, वीबीएबीएसएस के उपाध्यक्ष दूसी रामकृष्ण राव तथा विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री डॉ. पवन तिवारी आदि मौजूद थे। शिशु शिक्षा समिति असम के प्रचार संयोजक मुकुटेश्वर गोस्वामी ने गुवाहाटी में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से विद्या भारती के मास्टर ट्रेनर सहभागिता कर रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचपदी अधिगम पद्धति को अधिक प्रभावी बनाना तथा विद्या भारती संस्थानों में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। अपने संबोधन में वक्ताओं ने संस्कारयुक्त शिक्षा, नवीन शिक्षण पद्धतियों तथा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। कार्यशाला में आगामी दिनों में विभिन्न शैक्षणिक सत्र, व्यवहारिक प्रदर्शन, समूह चर्चा एवं संवादात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 मई तक चलेगा। यह कार्यशाला पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्या भारती विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण व्यवस्था एवं समग्र शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस पर एनएफआर का नुक्कड़ नाटक और पर्यावरण अभियान

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 15 मई से 5 जून तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। *जलवायु परिवर्तन* विषय पर आधारित इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश फैलाना है। इस अभियान के तहत पूसीरे के सभी मंडलों और इकाइयों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, संगोष्ठी और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों और आम जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। रेलवे स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, जल संरक्षण तथा रेलवे संचालन में हरित उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस अभियान में रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, स्काउट्स एवं गाइड्स तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में पूसीरे मुख्यालय, मालीगांव में पूसीरे स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति ने यात्रियों और आम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए पूसीरे के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच जूट बैग, कपड़े के थैले और जैविक रूप से नष्ट होने वाली वस्तुओं का वितरण भी किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लगातार पर्यावरण हितैषी उपायों को अपनाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल रेलवे संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभा रहा है। यह अभियान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों, जागरूकता गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण की शपथ के साथ संपन्न होगा।

असम में देखी गई दुर्लभ प्रजाति की बेंट-टोएड गेको छिपकली

ग्वालपाड़ा (हिंस)। असम के ग्वालपाड़ा जिले स्थित उरपाद बील (झील) में दुर्लभ प्रजाति की बेंट-टोएड गेको छिपकली (साइर्टोडैक्टिलस बापमे) देखी गई है। इसे राज्य की समृद्ध जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रजाति पहली बार असम में आधिकारिक रूप से दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों ने इस खोज को असम के वेटलैंड और वन पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि का महत्वपूर्ण संकेत बताया है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र अब भी कई दुर्लभ और कम ज्ञात प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने इस खोज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि असम की प्रकृति लगातार नए आश्चर्य प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उरपाद बील में बेंट-टोएड गेको का पहला पक्का रिकॉर्ड राज्य के इकोसिस्टम द्वारा समर्थित असाधारण जैव विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर संरक्षण प्रयास नाजुक आवासों को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं, जहां विभिन्न प्रजातियां फल-फूल रही हैं। उरपाद बील लंबे समय से अपने पारिस्थितिक महत्व के लिए जाना जाता है और यह कई जलीय एवं स्थलीय जीवों का प्राकृतिक आवास रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दुर्लभ गेको प्रजाति की मौजूदगी पर्यावरण संरक्षण और आवास सुरक्षा उपायों की सफलता को दर्शाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि बेंट-टोएड गेको साइर्टोडैक्टिलस वंश से संबंधित है, जो विश्वभर में गेको की सबसे विविध प्रजातियों में गिना जाता है। इस समूह की कई प्रजातियां सीमित आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं और पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील मानी जाती हैं। संरक्षणवादियों ने पूर्वोत्तर भारत के वेटलैंड, जंगल और अन्य प्राकृतिक इकोसिस्टम की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि दुर्लभ और स्थानिक वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय निगरानी बेहद आवश्यक है।–

ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने-सामने टक्कर में हुई तीन लोगों की मौत

गुवाहाटी (हिंस)। ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे छोर पर स्थित उत्तर गुवाहाटी के गौरीपुर क्षेत्र में बुधवार मध्य रात्रि को एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जॉयगुरु आश्रम के समीप हुआ। गौरीपुर पुलिस के अनुसार, गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक और स्कॉर्पियो वाहन के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर होने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंजीत दे, करुणा बेजबरुवा और पार्थ प्रतिम बर्मन के रूप में हुई है। इनमें एक व्यक्ति नावकाटा का निवासी था, जबकि अन्य दो गुवाहाटी के मालीगांव क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रक (एएस-01डीसी-3141) गलत दिशा से आ रहा था और उसने स्कॉर्पियो (एएस-01जीपी-9940) को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल रहा।

रंगिया नागरिक अस्पताल में फिर चोरी एसी के तार ले उड़े चोर, ऑपरेशन ठप

रंगिया (विभास)। रंगिया महकमा सिविल अस्पताल में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। इस बार चोरों ने अस्पताल में लगे एयर कंडीशनर के कीमती तारों पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 26 मई को अस्पताल प्रबंधन को इस चोरी का पता चला। एसी के तार चोरी होने के कारण अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते पिछले दो दिनों से सभी ऑपरेशन ठप पड़े हैं। इसके कारण दूर-दराज से इलाज कराने आए मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रंगिया के गैर-राजनीतिक संगठन *नागरिक मंच* का एक प्रतिनिधिमंडल तुरंत अस्पताल पहुंचा। मंच के सदस्यों ने इस घटना पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए अस्पताल अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। स्थानीय लोगों का कहना है कि रंगिया सिविल अस्पताल में चोरी की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में बार-बार स्थानीय प्रशासन और पुलिस को लिखित रूप से अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज तक सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। प्रशासन की इसी निष्क्रियता के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस ताजा घटना के बाद अस्पताल के उप अधीक्षक दिलीप कुमार बैश्य ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही अस्पताल अधिकारियों और *नागरिक मंच* के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और रात के समय पुलिस की गश्त (पेट्रोलिंग) को और अधिक सख्त किया जाए।

बरपेटा में 2.44 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

बरपेटा (हिंस)। बरपेटा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चला कर भारी मात्रा में हेरोइन और याबा टैबलेट समेत एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए गुरुवार को जारी एक पोस्ट में दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बरपेटा पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान 671 ग्राम हेरोइन और 22000 याबा टैबलेट जब्त किया गया है। जब्त किए गए हेरोइन और याबा टैबलेट की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.44 करोड रुपए आंकी गई है। घटना के संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस संबंध में एनडीपीएस धारा के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर से सघन पूछताछ कर रही है।

मेरापानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी तेज, 59 परिवारों में चिंता

गोलाघाट (हिंस)। असम के गोलाघाट जिले के मेरापानी क्षेत्र स्थित 2 नंबर नेघेरीबिल में एक बार फिर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने की तैयारी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन विभाग के विशेष मुख्य सचिव एमके यादव ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान वन विभाग, जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों की इस मौजूदगी के बाद इलाके में रह रहे 59 परिवारों के बीच चिंता का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की तैयारी की है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। गुरुवार के दौरे के दौरान अधिकारियों ने चिन्हित अतिक्रमित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मौजूदा स्थिति का आकलन किया। इस दौरान गोलाघाट की जिला आयुक्त पूवाली गोहाईं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जन दास और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वन विभाग की ओर से बताया गया है कि 2 नंबर नेघेरीबिल के 59 परिवारों और उरियामघाट के 11 परिवारों को पहले ही विस्थापन के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। विभाग के अनुसार, अदालत से अंतिम अनुमति मिलते ही जून के पहले हिस्से में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस संभावित कार्रवाई को लेकर इलाके में तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, वहीं प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं।

रंगिया : श्रीश्री राधाकृष्ण मंदिर संचालन समिति की नई कार्यकारिणी गठित

हरिराम क्याल को अध्यक्ष, मुकेश सिकरिया को सचिव की कमान और बासुदेव शर्मा बने कोषाध्यक्ष

रंगिया (विभास)। रंगिया के मध्य में स्थापित श्रीश्री राधाकृष्ण मंदिर संचालन समिति की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए बुधवार को मंदिर प्रांगण में एक चुनावी आम सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय सनातन समाज की भारी उपस्थिति के बीच संपन्न हुई इस चुनावी प्रक्रिया में हरिराम क्याल को अध्यक्ष, मुकेश सिकरिया को सचिव और बासुदेव शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। सभा की शुरुआत निवर्तमान अध्यक्ष महेश सिकरिया की अध्यक्षता में हुई। सबसे पहले सचिव प्रमोद अग्रवाल ने पिछली सभा का विस्तृत प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। इसके बाद कोषाध्यक्ष प्रदीप जाजोदिया ने अपने कार्यकाल का पूरा आय-व्यय का ब्यौरा सभा के सामने पेश किया। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद पुरानी समिति को भंग कर दिया गया और चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कमान चुनाव अधिकारी रतन सिकरिया और अनूप जाजोदिया को सौंपी गई। चुनाव अधिकारियों की देखरेख में नई कार्यकारिणी के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कोषाध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नाम सामने आने पर बासुदेव शर्मा को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया। वहीं, सचिव पद के लिए आशीष लुंडिया द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद मुकेश सिकरिया के नाम की घोषणा की गई। इसके पश्चात सबसे दिलचस्प मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए हुआ, जहां हरिराम क्याल और निवर्तमान अध्यक्ष महेश सिकरिया के बीच सीधा मुकाबला था। समाज बंधुओं द्वारा डाले गए कुल 112 वोटों के आधार पर बहुमत प्राप्त कर हरिराम क्याल ने जीत दर्ज की और समिति के नए अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान पूरे सनातन समाज ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई समिति मंदिर के विकास और सामाजिक कार्यों को और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएगी।

संपादकीय

हज के बाद जंग!

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप 'अच्छी खबर' तो दे नहीं सके और न ही ईरान के साथ समझौता कर पाए, लेकिन उनके लड़ाकू विमानों ने ईरान के नौसेना बेस पर तीन हमले जरूर कर दिए। इस तरह ट्रंप ने युद्धविराम तुड़वा दिया। अमरीकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमले कर ईरानी स्पीड नौकाओं को समंदर में डुबो दिया। मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हवाई हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। अमरीकी सेना की दलील है कि ईरानी नौकाएं समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं, लिहाजा आत्मरक्षा में अमरीका को हमले करने पड़े। इन हमलों और धमाकों में ईरानी आईआरजीसी के 4 जवान हताहत हुए और कुछ घायल भी हुए हैं। ईरान ने इसे युद्धविराम का 'साक्षात उल्लंघन' करार दिया है और अमरीका को 'महान शैतान' माना है। ईरान बेहद गुस्से में है। चूंकि यह 'पवित्र हज' का दौर है, दुनिया भर से 15 लाख से अधिक जायरीन हज यात्रा के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। भारत के जायरीनों (तीर्थयात्रियों) का अधिकृत कोटा भी 1.75 लाख से ज्यादा का है, लिहाजा ईरान किसी संभावित युद्ध के दोबारा आगाज के मद्देनजर खामोश है, लेकिन उसने हमलों की पुष्टि की है। युद्धविराम के दौरान अमरीका ने ऐसे हमले किए हैं, लिहाजा युद्धविराम टूट चुका है। सवाल है कि क्या हज के बाद युद्ध नए सिरे से छिड़ेगा? यह बेहद गंभीर, संवेदनशील, मानवीय सवाल है, क्योंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। हाहाकार मचा है। ऊर्जा के अलावा खाद्य संकट, उर्वरक संकट, माल के आयात-निर्यात का संकट और अंततः भुखमरी का संकट इस युद्ध के नतीजतन ही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और विश्व बैंक 'महामंदी' की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अमरीका और ईरान वैश्विक तबाही को आमादा हैं। अमरीका ने आदतन फिर दोगला प्रहार किया है। एक ओर कतर की राजधानी दोहा में कथित मध्यस्थ देश शांति-समझौते की रूपरेखा पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमरीकी सेना ने ईरानी पक्ष पर हमले किए हैं? यह किस किस्म की कूटनीति या शांति-संवाद है? राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते रहे हैं कि ईरान के साथ अमरीका की 95 फीसदी सहमति बन चुकी है। शेष 5 फीसदी पर बातचीत जारी है, लेकिन साथ में यह धमकी भी देते रहे हैं कि यदि ईरान ने करार नहीं किया, तो पहले से भी भयंकर हमले किए जाएंगे। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों, सहमतियों और सर्वोच्च यूरेनियम संबंधी बयानों को सिरे से खंडित किया है। अब हमलों के बाद और बकरीद के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का संदेश टीवी पर पढ़ा गया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अब खाड़ी देश अमरीकी सैन्य ठिकानों की 'ढाल' नहीं बनेंगे। अब खाड़ी का यह इलाका अमरीका के लिए 'सुरक्षित पनाहगाह' नहीं रहा है। खामेनेई ने मुस्लिम देशों को एकजुट होने और नई विश्व-व्यवस्था बनाने की अपील भी की है। हमलों के बाद ईरान ने पलटवार कर अमरीका के एम.क्यू.-9 ड्रोन (कीमत करीब 250 करोड़ रुपए) और आर.क्यू.-4 हॉक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमरीका के बेशकीमती एफ-35 फाइटर जेट पर भी मिसाइल से हमला किया गया है। इससे ईरान और सुप्रीम लीडर के मजबूत और आक्रामक मंसूबों को पढ़ा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के आकलन हैं कि हज के बाद, यानी आगामी 72 घंटों में, ईरान युद्ध नए सिरे से शुरू हो सकता है। यह भी आकलन है कि 3-4 महीने युद्धविराम का नाटक करने के बाद अमरीका सितंबर-नवंबर के दरमियान फिर हमला कर सकता है। तब तक राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू दबाव, मध्यावधि चुनावों का तनाव और अमरीका की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर जन-विरोध उतना नहीं रहेगा, जितना अब है। दोनों देशों के बीच समझौते के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि यूरेनियम, ईरान की जब्त संपत्तियों, पाबंदियों, हमले की क्षतिपूर्ति, होर्मुज जलमार्ग आदि अहम मुद्दे यथावत अनसुलझे रहे हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया खेल शुरू कर दिया है कि सभी खाड़ी देश और वार्ता में जुटे मुस्लिम देश 'अब्राहम समझौते' पर दस्तखत करें और इजरायल को मान्यता दें। खाड़ी के अधिकतर देश सन्नाटे में हैं, क्योंकि वे इजरायल के साथ किसी भी तरह के संबंधों के पक्षधर नहीं हैं।

ईरान ने इसे युद्धविराम का 'साक्षात उल्लंघन' करार दिया है और अमरीका को 'महान शैतान' माना है। ईरान बेहद गुस्से में है। चूंकि यह 'पवित्र हज' का दौर है, दुनिया भर से 15 लाख से अधिक जायरीन हज यात्रा के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। भारत के जायरीनों (तीर्थयात्रियों) का अधिकृत कोटा भी 1.75 लाख से ज्यादा का है, लिहाजा ईरान किसी संभावित युद्ध के दोबारा आगाज के मद्देनजर खामोश है, लेकिन उसने हमलों की पुष्टि की है। युद्धविराम के दौरान अमरीका ने ऐसे हमले किए हैं, लिहाजा युद्धविराम टूट चुका है। सवाल है कि क्या हज के बाद युद्ध नए सिरे से छिड़ेगा? यह बेहद गंभीर, संवेदनशील, मानवीय सवाल है, क्योंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। हाहाकार मचा है। ऊर्जा के अलावा खाद्य संकट, उर्वरक संकट, माल के आयात-निर्यात का संकट और अंततः भुखमरी का संकट इस युद्ध के नतीजतन ही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और विश्व बैंक 'महामंदी' की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अमरीका और ईरान वैश्विक तबाही को आमादा हैं। अमरीका ने आदतन फिर दोगला प्रहार किया है।

जनजातीय समाज अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनने को आतुर है

दिल्ली जनजातीय सम्मेलन- अस्मिता, अधिकार का आधुनिक उलगुलान

भील और भारिया की दो कहावतें हैं - भील कहते हैं, होने नी रेत, ने खोने नो डर और भारिया कहते हैं डोकरी मरिगे त कए घलो, बाकी राकस घर नई देखे। इन दो जनजातीय कहावतों में लालकिले से जनजातीय संदेश का सार छिपा है। भील कहावत का अर्थ है - जिसके पास सोने की रेत नहीं, उसे खोने का डर क्या? जनजातीय समाज के लिए, अब ये एक भूला-बिसरा चिंतन है। अब केवल भील नहीं अपितु देश के प्रत्येक जनजातीय, वनवासी, गिरिवासी समाज को पता है कि उसके पास खोने को एक स्वर्ण खदान से भी अधिक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। इस जनजातीय सांस्कृतिक संपदा, उनकी वन संपदा, उनकी श्रम संपदा का अनैतिक दोहन बहुत हुआ! और भारिया कहावत का अर्थ है - बुढ़िया मर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन राक्षस को घर का रास्ता नहीं देखना चाहिए। जनजातीय समाज ने संसद के समक्ष सीना ठोककर कहा - हमारे समाज को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों, ईसाईयत, इस्लाम और वामपंथी विचारकों रूपी 'राक्षस' ने जो लाल जाल बुना है, उसे अब हमने पहचान लिया गया है। अब हम उसे अपने घर की रह नहीं दिखायेंगे। लालकिले से यह जनजातीय उद्घोष है - अब दोहन, शोषण और नहीं, अब मतांतरण और नहीं, अब सनातन की आलोचना सहन नहीं, अब हमारी भाषा, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति, का विरूपण सहन नहीं। रविवार को दिल्ली के लालकिले पर संपन्न विशाल जनजातीय सम्मेलन केवल पारंपरिक वेशभूषा, मांदल, खजरी आदि की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि यह भारत के मूल समाज द्वारा अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की शंखध्वनि थी। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है सुदूर वनांचलों में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज अपनी जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए चतुर्दिक संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संवैचारिक, वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा कई दशकों से उठाए जा रहे मुद्दे अब राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं। सम्मेलन की गठी हुई भाषा और प्रखर स्वर ने यह साफ कर दिया कि जनजातीय समाज अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनने को आतुर है। लालकिले से वनवासी समाज ने प्रखरता, प्रचण्डता, प्रगल्भता और प्रबलता से 'डीलिस्टिंग' की अपनी पुरानी माँग का पुनरुद्घोष किया। आरएसएस सदा-सदा से यह कहता रहा है कि स्वधर्म छोड़कर ईसाइयत और इस्लाम को स्वीकारने वाले लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति से बाहर किया जाना चाहिए। ईसाई मिशनरियों ने व्यापक स्तर पर भोले-भाले जनजातीय समाज को बहला-फुसलाकर, आर्थिक लालच देकर, दबावपूर्वक; जैसे भी हो वैसे भी मतांतरण कराया है। देश में सतत चल रहे इस षड्यंत्रपूर्ण मतांतरण से झारखंड,

जनजातीय समाज ने संसद के समक्ष सीना ठोककर कहा - हमारे समाज को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों, ईसाईयत, इस्लाम और वामपंथी विचारकों रूपी 'राक्षस' ने जो लाल जाल बुना है, उसे अब हमने पहचान लिया गया है। अब हम उसे अपने घर की रह नहीं दिखायेंगे। लालकिले से यह जनजातीय उद्घोष है - अब दोहन, शोषण और नहीं, अब मतांतरण और नहीं, अब सनातन की आलोचना सहन नहीं, अब हमारी भाषा, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति, का विरूपण सहन नहीं। रविवार को दिल्ली के लालकिले पर संपन्न विशाल जनजातीय सम्मेलन केवल पारंपरिक वेशभूषा, मांदल, खजरी आदि की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि यह भारत के मूल समाज द्वारा अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की शंखध्वनि थी। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है सुदूर वनांचलों में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज अपनी जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए चतुर्दिक संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संवैचारिक, वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा कई दशकों से उठाए जा रहे मुद्दे अब राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं।

छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर राज्य में ऐसे अनगिनत उदाहरण हो गए हैं जहां धर्मांतरित लोग दोहरे लाभ उठा रहे हैं। वे एक ओर अल्पसंख्यक होने के नाते सरकारी योजनाओं और विदेशों से आने वाले भारी-भरकम फंड (FCRA) का लाभ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर जनजातीय कोटे से आईएएस, आईपीएस और अन्य ऊंचे पदों पर आसीन होकर विदेशी एजेंडे को लागू करते रहते हैं। यह कटु सत्य है कि अपनी मूल संस्कृति में रमे ठेठ वनवासी आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। सम्मेलन में सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई कि जो अपनी संस्कृति और पुरखों के देवी-देवताओं को छोड़ चुका है, वह जनजातीय कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। कुछ वर्षों से देश में कई प्रायोजित टूलकिट गिरोह सक्रिय हैं, जो जनजातीय समाज को बहका रही है कि तुम हिंदू नहीं हो, इसलिए जनगणना के फॉर्म में खुद को हिंदू मत लिखाना। लालकिले से जनजातीय समाज ने इस नैरेटिव का प्रखरता से खंडन किया है। यह षड्यंत्र मूलतः भारत की जड़ों को कमजोर करने का है। जनजातीय समाज प्रकृति पूजक है, और सनातन की आत्मा भी प्रकृति पूजा ही है। हम तुलसी, पीपल, सूर्य, नदी और गोवर्धन की पूजा करते हैं; और हमारे वनवासी भाई 'बूढ़ादेव', 'बड़ादेव' और जंगलों की पूजा करते हैं। शब्दों का अन्तर है, भाव हमारे एक हैं। भगवान राम के वनवास काल में निषादराज, शबरी और वानर-भालू (जो वनों के निवासी थे) उनके सहचर बने। भगवान शिव स्वयं 'किरात' (वनवासी) रूप धारण करते हैं। ऐसे में जनजातीय समाज को सनातन से अलग दिखाना एक गहरा जियोपालिटिकल षड्यंत्र है। यह भारत के भीतर 'सांस्कृतिक विभाजन' की नींव रखने का प्रयास है। दिल्ली के इस मंच से वक्ताओं ने झारखंड के संथाल परगना और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के अत्यंत विषैले व घातक पैटर्न को उजागर किया। असम और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जनजातीय महिलाओं को बहला-फुसलाकर या जबरन निकाह करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह प्रवृत्ति मप्र जैसे राज्यों में भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। चूंकि कानूनन कोई गैर-जनजातीय व्यक्ति जनजातीय की भूमि क्रय नहीं कर सकता, इसलिए इस कानून को धता बताने के लिए जनजातीय लड़कियों को मोहरा बनाया जाता है। निकाह के बाद जमीन उस महिला के नाम पर हस्तांतरित करा दी जाती है और परोक्ष रूप से उस भूमि पर नियंत्रण उस समुदाय का हो जाता है। झारखंड की रुबिका पहाड़नि या अंकिता सिंह जैसी बेटियों के उदाहरण अभी ताज़ा हैं। यह केवल एक सामाजिक अपराध नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी रणनीतिक जनसांख्यिकीय लड़ाई है जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वनवासी कल्याण आश्रम की प्रेरणा से ही मप्र में 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम' यानी पेसा कानून (PESA Act, 1996) का कार्य भली भाँति कार्य कर रहा है। पेसा कानून जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन पर संप्रभुता का अधिकार देता है। लेकिन दुखद यह है कि कई राज्यों में नियम न बनने के कारण या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह कानून केवल कागजों तक सीमित रहा। सम्मेलन में मांग की गई कि वन खनिजों की नीलामी, उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विवादों के निपटारे में ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य और सर्वोपरि बनाया जाए। इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिल रहे आरक्षण का लाभ सुदूर अंचलों में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए नीतियों के सरलीकरण पर जोर दिया गया। दिल्ली में हुआ यह जनजातीय सम्मेलन केवल माँग, शिकायत और आवेदनों का प्रकटीकरण नहीं था, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का घोषणापत्र था। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और जतरा भगत जैसी महान विभूतियों की विरासत को याद करते हुए इस बात पर संकल्प लिया गया कि अब जनजातीय समाज अपनी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि सरकारें, न्यायपालिका और नागरिक समाज इन चिंताओं को गंभीरता से लें। डीलिस्टिंग की मांग को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता, और न ही लव जिहाद या मिशनरी षड्यंत्रों को 'धर्मनिरपेक्षता' के चश्मे से देखकर नजरअंदाज किया जा सकता है। अपनी जड़ों की ओर लौटता और सजग होता यह वनवासी समाज आज देश की मुख्यधारा को दिशा दिखाने की स्थिति में है। यदि आज हम उनके जल, जंगल, जमीन और सबसे बढ़कर उनकी 'अस्मिता' की रक्षा करने में विफल रहे, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह सम्मेलन आधुनिक भारत में एक नए 'उलगुलान' (क्रांति) का शंखनाद है, जिसकी गूंज नीति-नियंताओं को लंबे समय तक सुननी होगी।

देश | दुनीया से

सरकारी स्कूलों की आपराधिक उपेक्षा क्यों

स्कूली शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 'नीति' आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह विडंबना ही है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली की धूल में नीति-आयोग की यह रिपोर्ट कहीं खो सी गयी है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सिर्फ चौंकाते ही नहीं, परेशान भी करते हैं। जैसे, यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी और निजी स्कूलों की स्थितियों का अंतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बता रहा है कि देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं कितनी खोखली हैं। प्रधानमंत्री एक से अधिक अवसरों पर अपने भाषणों में इस आशय के दावे कर चुके हैं कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मसलन, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में प्रति सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, हर रोज एक नया कॉलेज खुल रहा है। प्रधानमंत्री आईआईटी और आईआईएम के विस्तार के दावे भी कर चुके हैं। लेकिन नीति-आयोग की यह रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर रही है। पिछले एक दशक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट बता रही है कि हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकारी और गैर-सरकारी में बांटकर समूची शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में हम किस तरह की आपराधिक उपेक्षा बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए सन् 2017 और 2024 के बीच देश में 87000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गये, इसकी तुलना में निजी स्कूलों की जैसे बाढ़-सी आ रही है। यह सही है कि हाल के कुछ सालों में, विशेष कर कोरोना-काल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या

कुछ बढ़ी है, पर इसका कारण शिक्षा का स्तर नहीं, अभिभावकों की आर्थिक विवशता कहीं अधिक है। वैसे, यह भी एक विडंबना ही है कि आज देश में हमारी शिक्षा भी गरीब और अमीर में बंट गयी है। मान लिया गया है कि आर्थिक अभावों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की विवशता है कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं जहां पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है। आर्थिक स्थिति जरा-सी भी सुधरती है तो यह अभिभावक महंगे स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का यह बंटवारा हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को 'छोटे-बड़े' का अहसास दिलाने वाली हमारी शिक्षा-नीति एक तरह से शिक्षा के अधिकार के हमारे दावों को ही झुठला रही है। हम देश के हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस बारे में शायद सोचना ही नहीं चाह रहे। सन् 2021-22 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10,22,386 सरकारी और 3,35,844 निजी स्कूल हैं। यहां निजी स्कूल का मतलब महंगी पढ़ाई और बेहतर सुविधा है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि महंगी पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई ही हो– हां, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अभिभावक यह अहसास अवश्य जीते हैं कि उनका स्तर 'ऊंचा' है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बीमार सोच का पालन उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो समता-समानता के दर्शन वाले संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। 'पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया' का नारा देने वाले को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि 'इंडिया' क्या पढ़ रहा है? कैसी पढ़ाई कर रहा है। दुर्भाग्य से यह चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। नीति-आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हमारे स्कूलों की स्थितियों को तो अच्छे ढंग से दिखाया गया है, पर जिस तरह से यह रिपोर्ट अचर्चित ही रही है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर हमें दो तरह की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं देश के हर बच्चे को एक समान और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमारा छोटा-सा पड़ोसी देश नेपाल भी हमें कुछ सिखा सकता है। सुना है नेपाल की नई सरकार ने हाल ही में देश के सारे निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहां यह व्यवस्था की जा रही है कि सारी शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से दी जाये ताकि सब बच्चे एक जैसे स्तर की शिक्षा पा सकें। शिक्षा का अधिकार जितना ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी नहीं है शिक्षा का समुचित अवसर मिलना। शिक्षा को निजी और सरकारी में बांटने का मतलब अवसर की समानता के अधिकार को नकारना है। ज़रूरी है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता संवर्धन का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट पर देश में गहरा और व्यापक चिंतन हो। आज यह सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का अर्थ घटिया शिक्षा पाना ही क्यों माना जाता है? क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे बच्चे गर्व से कहें कि वे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूलों में पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, अच्छी साफ-सुथरी कक्षाएं हों– और बच्चों को पढ़ाने वाले सक्षम अध्यापक हों, इन अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों यह नहीं सोचा जाता कि एकल अध्यापक वाले स्कूल में बच्चे उचित शिक्षा कैसे पा सकते हैं।

आप का | नजरीया

चीन, पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती

पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार अपनी चीन यात्रा पूरी कर चुके हैं। गत बुधवार को बीजिंग में इसहाक डार ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। तीनों देशों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति जताई है। पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान में कहा- चीन और पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का अफगानिस्तान तक विस्तार करने का समर्थन किया है, चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्राभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने का भी समर्थन किया है। भारत सीपीईसी की आलोचना करता रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान प्राशासित कश्मीर से होकर गुजरता है। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है। इसलिए भारत इसका भी विरोध करता है। यह त्रिपक्षीय बैठक विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आमिर खान मुत्तकी से बातचीत के वुछ दिन बाद हुई है। हालांकि भारत नेअभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रावक्ता रणधीर जायसवाल से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, हमने वुछ रिपोट्र्स देखी है। इसके अलावा हमें इस बारे में और वुछ नहीं कहना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रावक्ता लिन जियान ने बीजिग में हुई इस बैठक को अनौपचारिक बताया है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने का स्पष्ट रुख व्यक्त किया है। चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास का समर्थन करता है। चीन साल 2021 में आने के बाद तालिबान सरकार के साथ राजनीतिक संबंध जारी रखने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इस मुलाकात को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ वूटनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में एक और कदम देखा जा सकता है। चीन-पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर करीब आते हैं तो भारत की विदेश नीति को एक और करार झटका लगता है। वैसे ही आपरेशन सिदूर ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि भारत की विदेश नीति, कोर नीति पूरी तरह से असफल ही है। इसका जीता जागत सुबूत है कि आपरेशन सिदूर के दौरान सिवाय इक्का-दुक्का देश के और कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। माने या न माने हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुरी तरह से पेल हो गए है और मोदी जी के लिए एक बोझ बन गए हैं जिन्हें बदलना अति आवश्यक हैं। प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संयुक्त दलों का प्रातिनिधिमंडल विदेश में भारत के स्टैंड को बताने का पैसला सराहनीय है। यह भी अच्छा कदम है कि इस व्राइसिस के समय पूरी पिछली सरकार और वेंद्र सरकार मिलकर काम करें। पाकिस्तान वूटनीति और विदेश नीति में हमारे से बेहतर रहा है। अब अगर चीन-पाक और तालिबान भी एक मंच पर आ जाते हैं तो भारत की चिता और बढ़ जाती है। दुर्भाग्य यह है कि तालिबान सरकार भूल गई है कि उसके पुनर्निर्माण में भारत ने कितनी मदद की और कर रही है। पर चीन के सामने शायद ही कोई टिक सके और चीन हमें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

तीनों देशों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति जताई है। पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान में कहा- चीन और पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का अफगानिस्तान तक विस्तार करने का समर्थन किया है, चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्राभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने का भी समर्थन किया है। भारत सीपीईसी की आलोचना करता रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान प्राशासित कश्मीर से होकर गुजरता है। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है। इसलिए भारत इसका भी विरोध करता है। यह त्रिपक्षीय बैठक विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आमिर खान मुत्तकी से बातचीत के वुछ दिन बाद हुई है। हालांकि भारत नेअभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रावक्ता रणधीर जायसवाल से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, हमने वुछ रिपोट्र्स देखी है। इसके अलावा हमें इस बारे में और वुछ नहीं कहना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रावक्ता लिन जियान ने बीजिग में हुई इस बैठक को अनौपचारिक बताया है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने का स्पष्ट रुख व्यक्त किया है। चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास का समर्थन करता है। चीन साल 2021 में आने के बाद तालिबान सरकार के साथ राजनीतिक संबंध जारी रखने वाले शुरुआती देशों में से एक था।

कुछ | अलग

उजले भविष्य के ध्वजवाहक

फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास 'मैला आंचल' का बावन दास तो आजकल तलाश किए कहीं नहीं मिलता। मिलते हैं तो अपने या अपने परिवार के हितों के दास। चार-चार पीढियां एक ही दल की बागडोर सम्भाले रहती हैं। उसकी अकूत धन-सम्पदा की एकमात्र ट्रस्टी बनी रहती हैं। लेकिन समय आने पर आम आदमी के दुख-दर्द की थाह लेने, उसकी दयनीय अवस्था पर आंसू टपकाते उन्हें देर नहीं लगती। अच्छे दिनों का अमृत बरस जाने का महोत्सव मना लिया। इसी बीच अकिंचन और भी फटीचर हो गए, लेकिन उनकी हालत न सुधर सकने का दोष विरोधी दल के मत्थे मढ़ दिया जाता है। हमने भी तो इस बीच एक लम्बी अवधि तक शासन किया। इस शासन में सबकी नहीं, अपने परिवार की हालत सुधारने पर बल दिया है। यही सूत्र चलता रहा कि राजा का बेटा अगर राजा हो सकता है, तो मंत्री का बेटा भी तो मंत्री ही होता है। आत्महत्या के बढ़ते हुए आंकड़े बताते हैं कि किसान का बेटा बदहाल किसान रहा, और मजदूर का बेटा वृक्ष से लटका हुआ खुदकुशी करता हुआ मिलता रहा है। ये आत्महत्याओं के आंकड़े इस देश में कम क्यों नहीं होते? देश में भुखमरी का सूचकांक भयावह रूप धारण करता चला जा रहा है, लेकिन नेता जी जो चाहे कुर्सीधारी हैं, या उनसे कुर्सी हथियाने के फेर में लगे हैं, केवल एक ही बात कहते हैं, आपकी भूख मिटाने के लिए हमारे पास सामुदायिक लंगर योजना तैयार खड़ी है। सर्वहितकारी राहतों और रियायतों की राजनीति के बल पर अपने हित की रक्षा के लिए दलबदल नेता अपने-अपने चेहरे की रौशनायी चमकाते रहते हैं।

दृष्टि | कोण

ऊर्जा की नई किरण भारत-ओमान समुद्री पाइपलाइन

होर्मुज जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिल पाई कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इस पर तेजी से काम करना शुरू किया है। हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पांच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी जरूरी होगा। सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है। इस पर पूर्व ओमान सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वेबसाइट 'मस्कट डेली' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए 'टेस्ट-सेक्शन' बिछा रहा है। 'सेज' ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी। इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग संभावनाओं की पुष्टि करना है। संभावना है कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियां गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश

देगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा। पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांजिट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊंची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है। इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है।

नए इनकम टैक्स कानून की बारीकियों पर सेमिनार आज

जोधपुर (हिंस)। आयकर विभाग की ओर से नए आयकर कानून 2025 के नियमों को समझाने के लिए एक खास सेमिनार किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 मई को सुबह 11.30 बजे पावटा सी रोड पर स्थित आयकर भवन के ग्राउंड फ्लोर पर होगा। संयुक्त आयकर आयुक्त (रेंज-1) कंचन राम मीना ने बताया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य टैक्स देने वाले कारोबारियों, उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और आम जनता को नए इनकम टैक्स कानून में हुए बदलावों व उसकी बारीकियों के बारे में जानकारी देना है। इस सेमिनार में जोधपुर आयकर विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे, जो आगंतुकों की शंकाओं का समाधान भी करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करके उसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया है। यह नया कानून इसी साल एक अप्रैल से पूरे देश में लागू हो चुका है। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, साफ-सुथरा और आम लोगों के लिए आसान बनाना है। नए कानून में पुरानी व्यवस्था के 819 सेक्शंस (धाराओं) को कम करके अब सिर्फ 536 कर दिया गया है। इसके साथ ही, कानूनी उलझनों को पूरी तरह खत्म करने के लिए नियमों की व्याख्या और अलग-अलग शर्तों को कानून की मुख्य कॉपी में ही शामिल कर दिया गया है, ताकि किसी को इसे समझने में कोई दिक्कत न हो। इस सेमिनार में मुख्य रूप से नए कानून के तहत किए गए बड़े बदलावों पर खुलकर चर्चा होगी। नए नियमों में असेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) और प्रीवियस ईयर (पिछले वर्ष) जैसे उलझाने वाले शब्दों को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। अब इनकी जगह सिर्फ टैक्स ईयर (कर वर्ष) का सीधा नियम काम करेगा। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि इस नए कानून से टैक्सपेयर्स पर पैसों का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा और न ही कोई नया टैक्स लगाया गया है। इसका पूरा फोकस सिर्फ टैक्स की भाषा को आसान बनाने, अर्थ को लेकर होने वाले विवादों को खत्म करने और लोगों को खुद आगे बढ़कर ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करना है।

सरकारी जमीन पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, बिहार सरकार ला रही नया कानून : मंत्री दिलीप जायसवाल

पटना (हिंस)। बिहार में सरकारी जमीन की हेराफेरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वालों पर अब शिकंजा और कसने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन का बंदरबांट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी जमीन गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम की गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द नया कानून लाने जा रही है। विभागीय मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुपौल, रोहतास और पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री दिलीप ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े हर काम को अब पूरी तरह ऑनलाइन मोड

में ही किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन तरीके से काम करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना है। इसके लिए योग्य परिवारों की पहचान कर उन्हें जमीन देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों में देरी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इसलिए लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन जरूरी है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने अंचल कार्यालयों में सक्रिय दलालों पर भी सख्त नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए आर्थिक अपराध इकाई का विशेष सेल बनाया गया है और विभाग के करीब पौने दो सौ अधिकारी उसकी निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री से लेकर नीचे तक हर स्तर पर ईमानदारी जरूरी है, तभी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। बैठक में म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन, राजस्व महाअभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर, फार्मर रजिस्ट्रेशन और आरसीएमएस से जुड़े लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने लंबे समय से लंबित मामलों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया। पटना जिले की रैंकिंग में सुधार पर विशेष जोर देते हुए मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को अगले 15 दिनों में स्पष्ट प्रगति दिखाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिले टॉप-10 में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ काम करें और जनता से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में विभागीय सचिव जय सिंह ने भी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।

चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर 70 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, शिक्षकों में रोष

फिरोजपुर (हिंस)। पंजाब के फिरोजपुर में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कथित तौर पर पोलिंग ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इनमें कई शिक्षक भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद शिक्षकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। एसडीएम-कम-रिटर्निंग ऑफिसर अभिषेक शर्मा ने इन कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 208 तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 120 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है। एफआईआर की सिफारिश के बाद जिन शिक्षकों के नाम सूची में शामिल हैं, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक यूनियनों ने प्रशासन पर उत्पीड़न, कुप्रबंधन और पोलिंग स्टाफ को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने चुनाव ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई और देर रात तक बैलेट बॉक्स जमा करवाए, इसके बावजूद उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया गया। शिक्षकों ने दावा किया कि मतदान समाप्त होने के बाद भी वे देर रात तक चुनाव प्रक्रिया में लगे रहे। बैलेट बॉक्स जमा करवाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद प्रशासन की ओर से उन्हें गैरहाजिर चिह्नित कर दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। शिक्षक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी निभाई है, उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए।यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

भारतीय परंपरा को जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक : दिलावर

जोधपुर (हिंस)। संस्कृत भारती राजस्थान क्षेत्र द्वारा भवानी आदर्श विद्या मंदिर पाल मार्ग में संचालित प्रशिक्षण वर्ग में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा को जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है। इस वेदवाणी का सामान्य जीवन में प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत को सीखना और सिखाना आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने वर्ग में चल रहे विविध आयामों का अवलोकन किया तथा संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संस्कृत भारती के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मंत्री ने वर्ग में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त की तथा उसकी प्रशंसा की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा, विशेषाधिकारी अभय सिंह राठौड़, क्षेत्र संगठन मंत्री कमल कुमार, क्षेत्र मंत्री तगसिंह राजपुरोहित, प्रशिक्षण प्रमुख राजेन्द्र शर्मा, वर्गाधिकारी रामनिवास शर्मा, वर्ग संयोजक लक्ष्मणसिंह गहलोत, पाबूराम विश्नोई, महेश दाधीच, मधुसूदन शर्मा, हरीश लोया, श्रीकिशन गहलोत, धर्मवीर सोनी, अशोक अग्रवाल, समाज सेवी शिवकुमार सोनी, ताराचंद रेपस्वाल, गणपत लाल शर्मा, दिनेश गौड़, मीना योगी, नरेंद्र कुमार टाक, राधाकृष्णन जाट, पुष्पेन्द्र शर्मा, ओमप्रकाश सियोल, सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष तुलसीदास शर्मा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

पंजाब में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के विभिन्न शहरों में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व मनाया गया। मलेरकोटला, संगरूर, मोहाली, जालंधर, लुधियाना आदि शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। लुधियाना की मुख्य जामा मस्जिद में शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने कहा कि यह पर्व आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। उन्होंने कहा कि ईद यह भी प्रेरणा देती है कि जब कभी देश को हमारे प्राणों की या धन दौलत की जरूरत हो तो उसे पेश किया जाए। लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम में नाइजीरिया के छात्र भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के पास मंदिर और गुरुद्वारा देखकर उन्हें बेहद खुशी होती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 स्थित मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी।

देवरिया में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा के लिए रोजगार मेला, 32 अभ्यर्थियों का चयन

देवरिया (हिंस)। स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवा में भर्ती हेतु रोजगार मेले का आयोजन शहर के महाराजा अग्रसेन कॉमर्स कॉलेज में किया गया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कुल 122 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 32 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया 31 मई तक जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) एवं एंबुलेंस चालक (पायलट) पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। ईएमटी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ईएमटी पद के लिए इंटरमीडिएट (बायोलॉजी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी विषय में स्नातक, एएनएम, जीएनएम, पीटीटी, बी-फार्मा अथवा 2 से 3 वर्षीय हेल्थकेयर संबंधित डिप्लोमा या डिग्री धारक अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ईएमटी पद हेतु साक्षात्कार 28 एवं 29 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक महाराजा अग्रसेन

कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देवरिया (मेडिकल कॉलेज के पास) में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं एंबुलेंस चालक (पायलट) पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एलएमवी/कमर्शियल/एचएमवी) एवं न्यूनतम तीन वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना जरूरी है। चालक पद के लिए भी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है। पायलट पद हेतु साक्षात्कार 30 एवं 31 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देवरिया में आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया 108 ईएमटीएस एवं 102 एमसीएस सरकारी एंबुलेंस सेवाओं के संचालन के लिए निजी संस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्था की मानव संसाधन नियमावली के अनुसार की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति के साथ साक्षात्कार में शामिल हों।

ससुराल बुलाकर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, आधी रात बना खौफ का मंजर

सीवान (हिंस)। जिले में बड़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में बुधवार की रात रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक को कथित तौर पर ससुराल बुलाकर पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घायल युवक की पहचान बालापुर निवासी नंदकिशोर रावत के पुत्र आदित्य कुमार रावत के रूप में हुई है। गंभीर रूप से झुलसे आदित्य ने बताया कि उसकी शादी पुरैना गांव में तय हुई है। बुधवार की सुबह होने वाले ससुराल से फोन कर उसे गांव बुलाया गया था। वह सीवान से, जहां वह काम करता है, दोपहर करीब तीन बजे पुरैना पहुंचा। आरोप है कि रात करीब साढ़े ग्यारह बजे आधा दर्जन लोगों ने उसे घेर लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई।

डॉ. अर्चना गुप्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर : डॉ. आशा खेदड़

हिसार (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता को भाजपा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में भारी उत्साह का माहौल है। भाजपा हिसार जिला अध्यक्ष डॉ. आशा खेदड़ सहित जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. अर्चना गुप्ता को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। जिला अध्यक्ष डॉ. आशा खेदड़ ने गुरुवार को कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता एक अनुभवी, कर्मठ एवं संगठन के प्रति समर्पित नेता हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन हरियाणा में और अधिक मजबूत होगा तथा पार्टी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता लंबे समय से पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ पूरे प्रदेश संगठन को मिलेगा तथा कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने डॉ. अर्चना गुप्ता के लंबे सांगठनिक अनुभव व पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, जो स्वागत योग्य है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सपड़ा, अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता के सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। जिला पदाधिकारियों ने विश्वास

जताया कि डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा हरियाणा में संगठनात्मक गतिविधियों को और गति मिलेगी तथा पार्टी जनसेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी।

पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : रणबीर

हिसार (हिंस)। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और हर व्यक्ति की आवाज़ को प्राथमिकता देना हरियाणा सरकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा अधिकारियों को भी जनहित के कार्यों में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा गुरुवार को यहां क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनकर सुझाव ले रहे थे। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट उनके कार्यालय में भिजवाई जाए ताकि समस्याओं के समाधान की नियमित समीक्षा की जा सके।

पंजाब चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा फैसला केवल सिंह ढिल्लों को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने बरनाला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केवल सिंह ढिल्लों को भाजपा पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ढिल्लों बरनाला से दो बार (2007 और 2012) विधायक रह चुके हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है। केवल ढिल्लों करीब चार साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अब वह पंजाब में भाजपा का सिख चेहरा होंगे। इससे पहले पार्टी ने सुनील जाखड़ को प्रधान बनाया था। गुरुवार को जिस समय केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया, उस समय वह चंडीगढ़ स्थित पंजाब लोक भवन में थे। भाजपा के कुछ नेता आज केवल सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मुलाकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ढिल्लों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2027 में पंजाब में कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। सारी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी है। मिलकर बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। केवल सिंह

ढिल्लों पंजाब के बरनाला जिला के तल्लेवाल गांव से हैं। उनका जन्म 16 मई 1950 को हुआ था। वह पंजाब के बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वह ढिल्लों ग्रुप के प्रमुख हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बरनाला में हुई थी। वह लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। कांग्रेस के टिकट पर वह 2007 और 2012 में बरनाला से विधायक चुने गए थे। 2017 में आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर ने उन्हें हराया था। जून 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए थे।

लोन भुगतान के बाद मकान के दस्तावेज जब्त नहीं रख सकता बैंक : हाईकोर्ट

प्रयागराज (हिंस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेटी की शादी के लिए संसाधन जोड़ रही मां के हक में फैसला सुनाते हुए बैंक ऑफ इंडिया में बंधक उसके मकान के बैनामा और अन्य दस्तावेजों को दो सप्ताह के अंदर सुपुर्द करने का आदेश दिया है। याची की ओर से उसका पक्ष अधिवक्ताओं ने रखा और दलील दी कि याची ने वर्ष 2002 में गाजियाबाद में एक मकान खरीदकर नगर निगम में नामान्तरण करवा लिया था। 10 वर्ष तक रहने के पश्चात 2012 में बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजकर बताया कि मकान की पूर्व मालकिन अपने बेटे के 5 लाख के लोन में गारंटर थी और मकान बंधक था। पूर्व मालकिन के बेटे द्वारा लंबे समय से लोन न चुकाने से अब देनदारी 22 लाख रुपए से ऊपर है और न चुकाने की स्थिति में बैंक द्वारा मकान का कब्जा ले लिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने बताया कि तत्कालीन बैंक मैनेजर द्वारा भी ये माना गया कि न तो अब गारंटर ही जीवित है और न ही उसके बेटे की कोई जानकारी है। बैंक द्वारा याची के साथ समझौता करते हुए 5,50,000 रुपए जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। किंतु गिरवी मूल दस्तावेज देने से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि बैंक द्वारा मूल उधारकर्ता अथवा गारंटर को ही उक्त कागज लौटाए जा सकते हैं। याची की ओर से तर्क दिया गया कि बैंक का आचरण मनमाना और अन्यायपूर्ण है। बैंक के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची बैंक का न ग्राहक है और न ही उधारकर्ता, इसलिए उसका गिरवी दस्तावेजों पर कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि याची की सम्पत्ति खरीद और नामांतरण पर बैंक द्वारा कोई आपत्ति कभी नहीं की गई और न ही उक्त सम्पत्ति पर कोई सिविल अथवा आपराधिक मामला लम्बित है। बैंक मानता है कि मूल गारंटर और उसके बेटे से सम्पर्क अब संभव नहीं है एवं समस्त लोन राशि समझौते के आधार पर चुका दी गई है। इसलिए अब बैंक के पास उक्त सम्पत्ति के गिरवी दस्तावेजों को रखने का कोई अधिकार नहीं है। याची अपनी बेटी की शादी हेतु दस्तावेजों के अभाव में लोन भी नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने बैक को दो हफ्ते में भवन के दस्तावेज अदेयता प्रमाणपत्र के आधार पर रिलीज करने का निर्देश दिया है।

उप्र में हर्षोल्लास से मनी बकरीद, मुस्लिम समाज ने की गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) पूरी अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की। इस बीच आगरा शहर से मुस्लिम समाज ने ईदगाह के बाहर *गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने* की मांग की और इसे भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश बताया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार त्योहार को लेकर सख्त गाइडलाइंस लागू की गई है। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में शुमार संभल में खास इंतजाम किए गए हैं। अन्य संवेदनशील जिलों में भी फ्लैग मार्च निकाले गए और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। बहरहाल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद पर्व मनाया जा रहा है। बकरीद (ईद-उल-अजहा) पर कुर्बानी और सड़क

पर नमाज पढ़ने को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तो कुछ तत्व गाय को ही कुर्बानी देने की बात कह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती और कानून व्यवस्था के बीच न तो कहीं सड़क पर नमाज पढ़ी गई और न ही खुले में कुर्बानी दी गयी। इस बीच प्रदेश की ताज नगरी से एक अनोखी पहल सामने आई है। आगरा के मुस्लिम समाज ने अपने पर्व बकरीद (ईद-उल-अजहा) की खुशी तो मनाई ही बल्कि नमाज अदा करने के बाद ईदगाह के बाहर *उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत* के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में तख्तियां और पोस्टर लेकर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो की मांग की। पदाधिकारियों का कहना था कि गाय देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। मुस्लिम महापंचायत के सरपंच नदीम नूर और अमजल कुरैशी ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करने के लिए उन्होंने इस पवित्र मौके पर यह मांग उठाई है। यह प्रदर्शन ईदगाह से निकलते नमाजियों और राहगीरों के बीच भारी कौतूहल और चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी और देश में अमन-चैन की दुआ मांगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती से प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद पर्व माना जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, संभल, बरेली, फर्रुखाबाद, कानपुर, औरैया, आगरा, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर समेत सभी जगहों में शांतिपूर्ण माहौल में मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गयी। इस मौके पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार त्योहार को लेकर सख्त गाइडलाइंस लागू की गई हैं। उन्होंने सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत देते हुए कहा कि था कि किसी भी सूरत में आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री के रुख के अनुरूप प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह ने लगातार समीक्षा बैठकें कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित किए। पुलिस ने जगह-जगह फ्लैग मार्च निकाला।

कोल इंडिया हिस्सेदारी बिक्री : निवेशकों के लिए आखिरी मौका

नई दिल्ली

भारत सरकार अपनी विनिवेश रणनीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। यह हिस्सेदारी बिक्री आफर फार सेल (ओएफएस) के माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत सरकार सीआईएल में 20 प्रतिशत तक की इक्विटी बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

मंगलवार को सरकारी माइनिंग कंपनी ने स्टाक एक्सचेंज फाइलिंग में इस संबंध में जानकारी साझा की। केंद्र सरकार ने इस ओएफएस के लिए प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य या फ्लोर प्राइस 412 रुपये निर्धारित किया है। यह मूल्य बीते कारोबारी दिन मंगलवार को कोल इंडिया के एनएसई क्लोजिंग प्राइस 455.90 रुपये से लगभग 10 प्रतिशत कम है, जो निवेशकों को रियायती दर पर सरकारी कंपनी के शेयर खरीदने का आकर्षक अवसर प्रदान करता है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कोल इंडिया के शेयर बेचकर 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाना है। ओएफएस के तहत केंद्र सरकार कोल इंडिया की कुल इक्विटी पूंजी के 1 प्रतिशत के बराबर 6.16 करोड़ शेयर बेच सकती है। इसके अतिरिक्त, ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति में सरकार ने इतने ही एक्स्ट्रा शेयर बेचने के लिए ग्रीन शू विकल्प अपने पास रखा है। इस प्रकार, कुल 12.32 करोड़ शेयरों की बिक्री हो सकती है, जो कंपनी में सरकार की 2 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। फ्लोर प्राइस के हिसाब से 1 प्रतिशत बेस हिस्सेदारी की बिक्री से ही सरकार को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की उम्मीद है, जबकि ग्रीन शू विकल्प का पूरा उपयोग होने पर यह राशि दोगुनी होकर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली बुधवार शुरू होगी, जबकि खुदरा निवेशक और पात्र कर्मचारी शुक्रवार, 29 मई को इसमें भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में कोल इंडिया की प्रमोटर बनी हुई है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अपनी विनिवेश रणनीति जारी रखे हुए है। यह ओएफएस आया है जब कोल इंडिया ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। मार्च में समाप्त तिमाही (वित्त वर्ष 2026) के लिए, कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत बढ़कर 10,908 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन राजस्व 6 प्रतिशत बढ़कर 46,490 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 5.25 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की भी घोषणा की है।

न्यूज ब्रीफ

छोटे कद के राइडर्स की पहली पसंद बनी ये बाइक्स

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में अब कम लंबाई वाले राइडर्स के लिए कम सीट हाइट वाली बाइक्स बेहतर विकल्प बनकर उभर रही हैं। कंपनियां अब ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर नए माडल पेश कर रही हैं, जिन्हें भारी और ऊंची बाइक चलाने में परेशानी होती है। टीवीएस राइडर 125 अपनी 780 एमएम सीट हाइट और हल्के वजन के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका 124.8 सीसी इंजन स्मूथ राइडिंग अनुभव देता है और ट्रैफिक में दोनों पैर आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं। वहीं रायल एनफील्ड हंटर 350 ने भारी-भरकम बाइक की पारंपरिक छवि बदल दी है। 790 एमएम सीट हाइट और काम्पैक्ट डिजाइन के कारण इसे शहर की सड़कों पर आसानी से चलाया जा सकता है। रायल एनफील्ड गोरिल्ला 450 भी कम सीट हाइट के साथ दमदार इंजन देने वाली खास बाइक मानी जा रही है। इसमें 452 सीसी इंजन के बावजूद सीट हाइट केवल 780 एमएम रखी गई है। टीवीएस रानिन भी 795 एमएम सीट हाइट और आरामदायक राइडिंग पोस्चर के कारण रोजाना उपयोग के लिए अच्छा विकल्प बन रही है।

मारुति सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस नई कार करेगी पेश

नई दिल्ली। भारत में जल्द ही मारुति सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस नई कार पेश करने वाली है। मारुति सुजुकी कंपनी ने संकेत दिए हैं कि पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 को वह ऐसी कार प्रदर्शित कर सकती है, जो ई-100 इथेनाल फ्यूल पर चलने में सक्षम होगी। कंपनी के मुताबिक इस वाहन में खास तरह का फ्यूल स्टोरेज, डिलीवरी और इग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे यह ई-100 ईंधन के अनुकूल बन सके। इथेनाल सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक नमी सोखता है, इसलिए इंजन और फ्यूल सिस्टम में विशेष बदलाव जरूरी होते हैं। इसी वजह से कंपनी ने इस तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया है। सरकार और आटो कंपनियां लंबे समय से इथेनाल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वदेशी ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। मारुति सुजुकी के अलावा टोयोटा, टाटा, महिंद्रा और सुजुकी सहित कुल 12 कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल वाहन प्रदर्शित कर चुकी हैं। वहीं होंडा और सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल टू-व्हीलर भी पेश कर चुकी हैं।

स्विगी का क्विक कामर्स में नया दांव, मुनाफा पहले, विस्तार बाद में

नई दिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते और प्रतिस्पर्धी क्विक कामर्स बाजार में स्विगी ने अपनी रणनीति में एक अहम बदलाव का संकेत दिया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की है कि स्विगी अब अनियंत्रित खर्च कर ग्राहकों की होड़ में शामिल होने के बजाय मुनाफे और टिकाऊ ग्राहक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस फैसले का मतलब है कि कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिलायंस रिटेल जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तरह हर कीमत पर विस्तार की दौड़ से पीछे हट रही है। उन्होंने बताया कि स्विगी अल्पकाल में कुछ ग्राहकों को खोने के लिए तैयार है, लेकिन उसका फोकस ऐसे ग्राहकों पर रहेगा जो लंबे समय तक जुड़े रहें और बेहतर कारोबार दें। जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां 10 मिनट डिलीवरी और भारी छूट के जरिए तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं, स्विगी ने इस खर्च की रेस में उतनी तेजी से शामिल न होने का निर्णय लिया है। निवेशक भी अब इंस्टामार्ट के लिए मजबूत ग्रोथ और मुनाफे का स्पष्ट रोडमैप चाहते हैं। स्विगी की इंस्टामार्ट यूनिट देशभर में 1,100 से अधिक डार्क स्टोर्स चलाती है, लेकिन मार्च तिमाही में केवल 7 नए स्टोर जोड़ना धीमी विस्तार गति का संकेत देता है। कंपनी का मानना है कि केवल खर्च बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इससे चुनौतियां आगे के लिए टल सकती हैं। ऐसे में स्विगी अब आक्रामक विस्तार के बजाय संतुलित और टिकाऊ बिजनेस माडल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बढ़ते ईंधन लागत के कारण एअर इंडिया 800 घरेलू उड़ानें घटाएगी, इंडिगो भी कर सकता है कटौती

नई दिल्ली

बढ़ते जेट फ्यूल की कीमतों और आपरेशनल लागत में वृद्धि के तहत, टाटा समूह की एअर इंडिया जून से अगस्त के बीच प्रति सप्ताह करीब 800 घरेलू उड़ानों में कटौती करने वाली है। यह एयरलाइन द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो उसकी कुल घरेलू उड़ानों का लगभग 22 प्रतिशत है। कंपनी ने फैसला जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों और संचालन में आ रही अन्य चुनौतियों के कारण लिया है। इसी बीच, रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी अपनी घरेलू उड़ानों में 5 से 7 प्रतिशत तक की कमी कर सकती है, जिससे भारतीय हवाई यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

एअर इंडिया वर्तमान में प्रति सप्ताह करीब 4400 उड़ानें संचालित करती है, जिसमें से करीब 3600 घरेलू और 800 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि वह बाजार की मांग और आपरेटिंग परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखेगी और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य व स्थिर होंगी, उड़ानों की संख्या को दुबारा बहाल करने पर विचार होगा। इन कटौतियों का मुख्य कारण 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों के बाद मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष है, जिससे वैश्विक जेट फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, ईरानी हवाई क्षेत्र के उपयोग से बचने के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग लंबे हुए हैं और पाकिस्तानी एयरस्पेस पर जारी पाबंदियों ने भी परिचालन लागत को बढ़ाया है। इंटरनेशनल आटोमोबाइल फेडरेशन (एफआईए) के आंकड़ों के मुताबिक, एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा पहले 40 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह वित्तीय दबाव एयरलाइंस के नेटवर्क को वित्तीय रूप से अस्थिर बना रहा है। एयरलाइंस पर दबाव पहले से ही दिख रहा था। एविएशन एनालिटिक्स फर्म के आंकड़ों के अनुसार, मार्च और अप्रैल में भारत की चार सबसे बड़ी एयरलाइंस के संचालन में पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इस दौरान, इंडिगो ने 4.5 प्रतिशत और एअर इंडिया ने 7.5 प्रतिशत कम उड़ानें संचालित कीं, जबकि एअर इंडिया की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा 17.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

परिचालन लागत बढ़ने से एयरलाइंस ने इसका बोझ यात्रियों पर डाल दिया है, जिससे हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है। किराए बढ़ने से घरेलू हवाई यात्रा की मांग में भी कमी आई है, जिससे उद्योग को दोहरी मार पड़ रही है। वर्तमान में, भारतीय घरेलू हवाई यात्रा बाजार पर इंडिगो और एअर इंडिया का दबदबा है, जिनका संयुक्त बाजार हिस्सा करीब 90 प्रतिशत है।

ग्राहकों में मिड साइज एसयूवी एमजी हेक्टर लोकप्रिय

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एमजी मोटर्स की मिड साइज एसयूवी एमजी हेक्टर लोकप्रिय बनी हुई है। ग्राहक इस एसयूवी को करीब दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर ला सकता है। कंपनी की ओर से हेक्टर के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है। दिल्ली में इसकी आन रोड कीमत करीब 13.87 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसमें आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस और टीसीएस चार्ज भी शामिल हैं। यदि ग्राहक दो लाख रुपये डाउन पेमेंट करता है, तो बाकी करीब 11.87 लाख रुपये का फाइनेंस करवाना होगा। अगर बैंक सात साल की अवधि के लिए नौ फीसदी ब्याज दर पर लोन मंजूर करता है, तो ग्राहक को हर महीने लगभग 19,110 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी। इस तरह सात साल में कुल ब्याज करीब 4.17 लाख रुपये हो जाएगा। ब्याज और आन रोड कीमत जोड़ने पर इस एसयूवी की कुल लागत करीब 18.05 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। एमजी हेक्टर को भारतीय बाजार में टाटा सफारी, महिंद्रा स्कार्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्स0, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी से कड़ी टक्कर मिलती है।

बेमौसम मार के बावजूद रिकार्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान : सरकार

नई दिल्ली

देश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बावजूद सरकार ने फसल सत्र 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान लगाया है। कृषि मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह उत्पादन 2.29 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 12.06 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले अनुमानों के अनुरूप है।

2025-26 में 12.06 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद

कृषि मंत्रालय ने जुलाई 2025-जून 2026 सत्र के लिए प्रमुख कृषि फसलों का अपना तीसरा अनुमान जारी करते हुए कहा कि गेहूं का अनुमानित उत्पादन पिछले फसल सत्र 2024-25 के 11.79 करोड़ टन से 27.12 लाख टन अधिक होगा। मंत्रालय ने दोहराया कि कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के बावजूद देश का गेहूं उत्पादन स्थिर और मजबूत बना रहेगा। यह आशावाद सरकारी खरीद लक्ष्यों में वृद्धि से भी झलकता है, जहां इस सीजन में किसानों से 345 लाख टन गेहूं खरीदने का फैसला किया गया है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से 15 प्रतिशत अधिक है। अब तक 340 लाख टन की खरीद हो चुकी है। हालांकि, निजी अनुमान 2025-26 में उत्पादन लगभग 11.06 करोड़ टन रहने का संकेत देते हैं, जो सरकारी आंकड़ों से कम है। कुल मिलाकर, 2025-26 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 37.66 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 35.77 करोड़ टन से काफी अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बंपर उत्पादन का स्वागत करते हुए इसे सरकार की कृषि नीतियों का सकारात्मक परिणाम बताया।

हिमालया बेबीकेयर ने गोल्डन बेबी गिफ्ट पैक लान्च किया

इंदौर। देश के प्रमुख शिशु देखभाल ब्रांड हिमालया बेबीकेयर ने बुधवार को भारतीय बाजार में अपना नया उत्पाद हिमालया गोल्डन बेबी गिफ्ट पैक लान्च करने की घोषणा की। भारतीय संस्कृति में नवजात शिशुओं को उपहार देने की परंपरा और सोने को समृद्धि का प्रतीक मानने की भावना से प्रेरित इस पैक को एक आकर्षक गोल्ड थीम में पेश किया गया है। इसकी कीमत 501 निर्धारित की गई है। कंपनी के बेबीकेयर निदेशक चक्रवर्ती एन.वी. ने बताया कि इस प्रीमियम पैक में जेंटल बेबी सोप (125 ग्राम), बेबी लोशन (100 मिली), बेबी पाउडर (100 ग्राम), बेबी मसाज आयल (50 मिली), जेंटल बेबी शैम्पू (50 मिली) और एक सूती तौलिया शामिल है। यह उत्पाद नवजात शिशुओं की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी कोमल त्वचा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। लान्चिंग के साथ ही कंपनी ने हिमालया गोल्डन मोमेंट्स प्रोग्राम नामक डिजिटल अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत माता-पिता अपने बच्चों की अनमोल यादें और तस्वीरें साझा कर 1 लाख रु. का गोल्ड वाउचर या 10 हजार रु. का सिल्वर वाउचर जीत सकते हैं। रिटेल और डिजिटल प्लेटफार्म पर इस अभियान में भाग लेने की प्रक्रिया को क्यूआर कोड और व्हाट्सऐप के जरिए बेहद सरल बनाया गया है।

सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट जारी, चांदी के भाव में बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के भाव में कमजोरी का रुख लगातार जारी है। हालांकि चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने की कीमत में आई कमजोरी के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में शुरुआती कारोबार के दौरान ये चमकीली धातु 550 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो गई है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत में शुरुआती कारोबार के दौरान 800 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,58,280 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,59,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,45,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,58,430 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,58,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,58,330 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,59,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,46,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,58,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,45,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जिलेट इंडिया का दमदार मुनाफा, शेयरधारकों को 60 डिविडेंड का ऐलान

मार्च तिमाही में लाभ 21 फीसदी बढ़कर 192.5 करोड़ हुआ

नई दिल्ली

जिलेट इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2026 तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने सालाना आधार पर अपने मुनाफे में 21 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए शेयरधारकों हेतु प्रति इक्विटी शेयर 60 रुपए के अंतिम डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 60 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। यह आगामी 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

मंजूरी उपरांत, भुगतान 18 सितंबर 2026 तक कर दिया जाएगा। मार्च 2026 तिमाही में जिलेट इंडिया का मुनाफा 21.3 फीसदी बढ़कर 192.5 करोड़ रुपये रहा। आपरेशंस से आय

792 करोड़ रुपये दर्ज हुई। एबिटा 12.4 फीसदी बढ़कर 277 करोड़ रुपये और एबिटा मार्जिन 35 फीसदी पर पहुंचा। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 3100 करोड़ रुपये, जबकि शुद्ध लाभ 23 फीसदी बढ़कर 654 करोड़ रुपये रहा।

जेब से स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी, सरकार का अंशदान घटा

नई दिल्ली। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें लोगों द्वारा सीधे अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर-ओओपीई) भी बढ़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में ओओपीई एक साल में 39.4 फीसदी (2021-22) से बढ़कर 43.4 फीसदी हो गया है। इसी अवधि में, स्वास्थ्य पर सरकार का अंश 48 फीसदी से घटकर 43.7 फीसदी रह गया है। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमानों में ओओपीई में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़ती लागतों की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 महामारी के बाद पूर्ण रूप से खुलने के पहले साल (2022-23) में स्वास्थ्य, निदान और फार्मास्यूटिकल्स की उच्च लागत और मांग के कारण ओओपीई में यह वृद्धि हुई है। हालांकि, व्यापक तौर पर देखा जाए तो 2013-14 में दर्ज किए गए 64.2 फीसदी की तुलना में घरेलू खर्च में दशक के आधार पर गिरावट आई है, जो केंद्र के वित्त वर्ष 2025-26 तक ओओपीई को 35 फीसदी तक कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है। फिर भी, हालिया वार्षिक वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है।

नार्वे चेस 2026 : तीसरे दौर में बड़ा उलटफेर प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया

गुकेश ने फिरोजा से ड्रा खेला, दिव्या देशमुख ने आर्मागेडन में दर्ज की जीत

ओस्लो (नार्वे)

नार्वे चेस 2026 के तीसरे दौर में बुधवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। ओस्लो में खेले गए मुकाबले में प्रज्ञानानंद ने शानदार रणनीतिक खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल मुकाबले में जीत दर्ज की। मैच के अधिकांश समय तक प्रज्ञानानंद मजबूत स्थिति में नजर आए। हालांकि समय के दबाव में कुछ समय के लिए मुकाबले का रुख कार्लसन की ओर जाता दिखा, लेकिन इसके तुरंत बाद नार्वे के स्टार खिलाड़ी ने बड़ी गलती कर दी और उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी।

फिरोजा ने बरकरार रखी बढ़त

विश्व चैंपियन डी. गुकेश और टूर्नामेंट लीडर अलीरेजा फिरोजा के बीच क्लासिकल मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा और अंततः ड्रा पर समाप्त हुआ। इसके बाद खेले गए आर्मागेडन मुकाबले में फिरोजा ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक हासिल किए और तालिका में अपनी बढ़त कायम रखी। वहीं विंसेंट कीमर और वेस्ली सो के बीच भी क्लासिकल मुकाबला ड्रा रहा। बाद में आर्मागेडन गेम में वेस्ली सो ने जीत दर्ज की। तीसरे दौर के बाद अलीरेजा फिरोजा अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।

नार्वे चेस महिला वर्ग में भी रोमांच जारी

नार्वे चेस विमेंस टूर्नामेंट में भी सभी क्लासिकल मुकाबले ड्रा रहे, जिसके बाद विजेता का फैसला आर्मागेडन मुकाबले से हुआ। महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन और झू जिनेर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एक समय झू जिनेर मजबूत स्थिति में थीं, लेकिन वह उसे जीत में नहीं बदल सकीं। बाद में आर्मागेडन में झू जिनेर ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक हासिल किए। अन्ना मुजिचुक और भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रा रहा। इसके बाद आर्मागेडन में अन्ना मुजिचुक ने जीत हासिल की। वहीं टूर्नामेंट लीडर बिबिसारा अस्साउबायेवा और भारत की दिव्या देशमुख के बीच भी क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर छूटा। इसके बाद दिव्या देशमुख ने शानदार खेल दिखाते हुए आर्मागेडन मुकाबले में जीत दर्ज की।

न्यूज़ ब्रीफ

फ्रेंच ओपन 2026: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आसानी से पार किया दूसरा दौर, सीधे सेटों में दर्ज की जीत

पेरिस। दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को दूसरे दौर में चेक गणराज्य के टामस मचाक को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। रोलां गैरो के कोर्ट फिलिप शात्रिए पर खेले गए मुकाबले में ज्वेरेव ने मचाक को 6-4, 6-2, 6-2 से मात दी। अब तीसरे दौर में उनका सामना मेजबान फ्रांस के क्वेंटिन हालीस से होगा। मैच के बाद ज्वेरेव ने कहा, मैं अपने खेल से काफी संतुष्ट हूं। मेरा आत्मविश्वास अच्छा है और मैं आगे के मुकाबलों को लेकर उत्साहित हूं। उम्मीद है कि मैं फिर इसी कोर्ट पर खेलने लौटूंगा। विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर मौजूद टामस मचाक मैच के दौरान फिटनेस से जूझते नजर आए। दूसरे सेट में उन्हें बाएं पैर में परेशानी के कारण लंबा मेडिकल टाइम-आउट लेना पड़ा। ज्वेरेव ने कहा, डेढ़ सेट तक मुकाबले का स्तर काफी शानदार था, लेकिन चोट के कारण मैच की लय थोड़ी टूट गई। मैं खुश हूं कि मुकाबला तीन सेट में समाप्त कर सका। विश्व नंबर-3 ज्वेरेव ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और केवल एक ब्रेक प्वाइंट बचाते हुए महज 1 घंटा 48 मिनट में जीत दर्ज कर ली। गौरतलब है कि ज्वेरेव ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के सबसे करीब पेरिस में ही पहुंचे हैं। पिछले पांच वर्षों में वह लगातार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, जबकि 2024 के फाइनल में उन्हें कार्लोस अल्काराज के खिलाफ पांच सेटों में हार का सामना करना पड़ा था ।

टी20 विश्वकप जीतने के इरादे से उतरेगी दक्षिण अफ्रीका : वोल्वार्ट

जोहांसबर्ग। हाल ही में भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज जीत से उत्साहित दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ट अब अगले माह इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्वकप को जीतना चाहती हैं। वोल्वार्ट का कहना है कि उनकी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और वह खिलाब जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पिछले कुछ साल में लगातार सुधार किया है। वह साल 2023 और 2024 में लगातार दो टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इसके अलावा, टीम पिछले साल एकदिवसीय विश्व कप में भी उपविजेता रही थी। लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद भी खिताब हासिल नहीं कर पाने की निराशा से टीम नहीं है और उसके अंदर जीत का जज्बा बढ़ा है। वोल्वार्ट ने लिखा, लगातार दो बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचना निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद खास रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर दिया है। उनकी टीम को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। गौरतब है कि इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले, दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल में पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारतीय टीम को 4-1 से हरा दिया था। वोल्वार्ट के अनुसार, भारत के खिलाफ सीरीज दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ अपने को आंकने का एक शानदार अवसर था। उस सीरीजको जीतने से टीम का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने टीम की क्षमता और जुझारूपन को दिखाय।

27 जुलाई से दिल्ली में होगी राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, 35 से अधिक देशों के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की संभावना

नई दिल्ली। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। इस दौरान रोमांचक मुकाबले होने की संभावना है। इस चैम्पियनशिप का आयोजन दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें 35 से अधिक देशों के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है, जो इस आयोजन को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाएगा। इस चैंपियनशिप न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी बल्कि दिल्ली को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल गंतव्य के रूप में भी स्थापित करेगी। सात दिवसीय इस चैम्पियनशिप में दुनिया भर के टेबल टेनिस खिलाड़ी भी भाग लेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्काटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे राष्ट्रों के खिलाड़ी अपनी खेल भावना और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।

यूनिटी कप 2026 : जमैका से हारा भारत, अब जिम्बाब्वे से होगा तीसरे स्थान का मुकाबला

सेमीफाइनल में 0-2 से मिली हार, नौफाल पीएन और रिकी शाबोंग ने किया भारतीय टीम के लिए पदार्पण

लंदन

यूनिटी कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय फुटबाल टीम को बुधवार की जमैका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। द वैली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जमैका के ए कोर्टनी क्लार्क और काहीम डिक्सन ने गोल दागे।

इस जीत के साथ जमैका ने फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना नाइजीरिया से होगा। नाइजीरिया ने पहले सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया था। वहीं भारतीय टीम अब 30 मई को तीसरे स्थान के मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी।

भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास रहा मुकाबला

इस मैच में भारत के लिए कई खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। नौफाल पीएन और रिकी शाबोंग ने सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया, जबकि एडमंड लालरिंदिका को पहली बार शुरुआती एकादश में मौका मिला।

भारत 2002 के बाद पहली बार ब्रिटिश धरती पर कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहा था, लेकिन टीम मैच में शुरुआत से ही लय हासिल नहीं कर सकी।

मैच के आठवें मिनट में जमैका ने तेज पलटवार किया। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पहले शानदार बचाव किया, लेकिन भारतीय डिफेंस गेंद को पूरी तरह क्लियर नहीं कर सका। कोर्टनी क्लार्क ने ढीली गेंद पर कब्जा जमाते हुए शानदार शाट के जरिए गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी कोने में पहुंचा दिया। फीफा रैंकिंग में 71वें स्थान पर मौजूद जमैका ने इसके बाद लगातार आक्रामक खेल जारी रखा। 17वें मिनट में काहीम डिक्सन के पास बढ़त दोगुनी करने का मौका था, लेकिन गुरप्रीत ने बेहतरीन बचाव कर भारत को मैच में बनाए रखा। पहले हाफ के अंतिम हिस्से में भारत ने कुछ बेहतर पासिंग दिखाई, लेकिन अंतिम तिहाई में टीम की कमी साफ नजर आई। रयान विलियम्स, लालियांजुआला छांगते और एडमंड लालरिंदिका प्रभाव छोड़ने में असफल रहे।

दूसरे हाफ में भारत ने दिखाई वापसी की कोशिश

हाफ टाइम के बाद भारतीय टीम ज्यादा आक्रामक नजर आई। 53वें मिनट में भारत को बराबरी का शानदार मौका मिला, जब जमैका के डिफेंस और गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए रोशन ने रहीम अली को पास दिया। हालांकि रहीम अली आफसाइड पाए गए और छांगते का गोल मान्य नहीं हुआ। इसके बाद भारत ने मैच में वापसी की कोशिश तेज कर दी। कोच खालिद जमील की टीम ने ऊंची लाइन पर खेलते हुए जमैका पर दबाव बनाया और कुछ समय के लिए मैच का नियंत्रण अपने हाथ में लिया।

काहीम डिक्सन ने खत्म की भारत की उम्मीदें

जब भारत वापसी की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी 78वें मिनट में काहीम डिक्सन ने शानदार व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करते हुए मैच का दूसरा गोल दाग दिया। उन्होंने बाक्स के बाहर से शानदार मूव बनाते हुए आकाश मिश्रा को छकाया और गेंद को गुरप्रीत सिंह संधू के पास से निकालकर गोल में पहुंचा दिया।

श्रीलंकाई प्रीमियर लीग में खेलते दिखेंगे आलराउंडर विजय शंकर

कोलंबो

भारतीय टीम के पूर्व आलराउंडर विजय शंकर अब श्रीलंकाई प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट क्रिकेट में खेलते हुए नजर आयेंगे। श्रीलंकाई प्रीमियर लीग (एलपीएल) का छठा सत्र 17 जुलाई से 8 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंकाई प्रीमियर लीग की ओर से 1 जून को होने वाले प्लेयर ड्राफ्ट के लिए बड़े नामों की सूची जारी कर दी गई है। कैंडी रायल्स टीम की इसके लिए जारी सूची में विजय शंकर का नाम सबसे पहले शामिल है। विजय के अलावा इंग्लैंड के मोईन अली और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन भी इस लीग में खेलेंगे। इन दोनो को ही इसकी संबंधित फ्रेंचाइजियों ने रिटेन किया है, जिससे इस सत्र में रोमांचक प्रतिस्पर्धा की उम्मीद जतायी जा रही है। साल 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल रहे विजय शंकर ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर रिकार्ड बनाया था। वह कैंडी रायल्स की टीम की ओर से खेलेंगे। उनके आने से उत्साहित लीग की आरे से कहा गय कि तमिलनाडु के इस तेज गेंदबाज आलराउंडर के आने से कैंडी की टीम और बेहतर हुई है। इस टीम में मोईन अली के साथ-साथ श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और वानिंदु हसरंगा भी शामिल हैं। विजय शंकर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब वह अंतरराष्ट्रीय लीग खेलते दिखेंगे। उन्होंने साल 2018 और 2019 के बीच भारत की ओर से 12 एकदिवसीय और नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। आईपीजी ग्रुप के संस्थापक और सीईओ अनिल मोहन संखधर ने लीग के बढ़ते प्रभाव को लेकर कहा, श्रीलंका प्रीमियर लीग लगातार दुनिया के प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देशों से बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो वैश्विक टी20 लीग के बढ़ते कद को दिखाता है। विजय शंकर, मोईन अली, शाकिब अल हसन और श्रीलंका के कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों के इस सीजन में शामिल होने से इसमें उच्च गुणवत्ता वाला क्रिकेट देखने को मिलेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए ये एक मजबूत मंच के रूप में उभर रहा है। हमारा मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशिया में लीग की उपस्थिति को मजबूत करना है, साथ ही खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना है। पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन और एलपीएल के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी, एससी जाफना किंग्स ने भी अपनी टीम को बेहतर बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन के साथ-साथ श्रीलंकाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दुनिथ वेलालगे और भानुका राजपक्षे को रिटेन किया है।

मटेता के गोल से क्रिस्टल पैलेस ने जीता पहला यूरोपीय खिताब

लीपजिग। जीन-फिलिप मटेता के दूसरे हाफ में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत क्रिस्टल पैलेस ने बुधवार रात यूईएफए कान्फ्रेंस लीग फाइनल में रायो वायेकेनो को 1-0 से हराकर क्लब इतिहास का पहला यूरोपीय खिताब अपने नाम कर लिया। यह जीत टीम के मैनेजर ओलिवर ग्लासनर के लिए भी शानदार विदाई साबित हुई। क्रिस्टल पैलेस को घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन के आधार पर शुरुआत में यूरोपा लीग में जगह मिली थी, लेकिन यूईएफए के मल्टी-क्लब ओनरशिप नियमों के चलते टीम को कान्फ्रेंस लीग में भेज दिया गया। हालांकि टीम ने इसे निराशा नहीं बनने दिया और पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए यूरोपीय मंच पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। मैच का निर्णायक क्षण 51वें मिनट में आया, जब एडम व्हार्टन के लंबी दूरी के शाट को रायो गोलकीपर आगस्तो बताला पूरी तरह रोक नहीं सके। गेंद उनके हाथों से छिटककर मटेता के पास पहुंची और फ्रांसीसी स्ट्राइकर ने करीब से आसान गोल दागते हुए क्रिस्टल पैलेस को बढ़त दिला दी।

जून में होगा रग्बी महिला प्रीमियर लीग का आयोजन

16 से 28 जून तक हैदराबाद के गचीबाउली स्टेडियम में होंगे मुकाबले

हैदराबाद

रग्बी महिला प्रीमियर लीग (आरपीएल) मुकाबलों का आयोजन अगले माह जून में होने जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस लीग के आयोजन से देश में महिला रग्बी खिलाड़ियों को प्रौत्साहन मिलेगा। हैदराबाद के गचीबाउली स्टेडियम में ये टूर्नामेंट 16 से 28 जून तक खेला जागा। इसमें चार फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए टकरायेंगी। इनमें चेन्नई बुल्स, दिल्ली रेड्ज, मुंबई ड्रीमर्स और कोलकाता बंगा टाइगर्स शामिल हैं। इन लीग को प्रतिष्ठित कार्पोरेट घरानों के समर्थन से भी लाभ होगा।

इस लीग का आयोजन जीएमआर स्पोर्ट्स और रग्बी इंडिया मिलकर कर रहे है। ये दोनो ही देश में रग्बी के विकास और प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन एक रोमांचक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। चार महिला टीमों और छह पुरुष टीमों (जिनमें मेजबान हैदराबाद हीरोज और बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स जैसे नाम शामिल हैं) के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट और नीलामी 30 अप्रैल को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इस लीग से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। पिछले साल मुंबई में रग्बी प्रीमियर लीग के पहले सफल सत्र का आयोजन किया गया था, और अब महिला टूर्नामेंट की शुरुआत से लीग का दायरा और महत्व काफी बढ़ गया है। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने इस ऐतिहासिक पहल पर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, रग्बी इंडिया में हमारा हमेशा से यह सपना रहा है कि आरपीएल का महिला टूर्नामेंट भी हो। इस साल हमारा वह सपना पूरा हो रहा है और हम इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह महिला एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा, साथ ही देश में रग्बी के प्रति जुनून को और बढ़ाएगा।

आईपीएल 2026 : सूर्यवंशी ने आरेंज कैप पर जमाया कब्जा, रनों की दौड़ में बने नंबर-1

राजस्थान रायल्स के युवा बल्लेबाज ने तोड़े कई रिकार्ड, जोफ्रा आर्चर भी पर्पल कैप की रेस में मजबूत

नई दिल्ली

राजस्थान रायल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार रात विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आरेंज कैप अपने नाम कर ली। उनकी तूफानी पारी ने राजस्थान को क्वालिफायर-2 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वैभव सूर्यवंशी ने मैच में सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 छक्के लगाए और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकार्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी सबसे तेज आईपीएल शतक के रिकार्ड के भी करीब पहुंच गए थे। यह रिकार्ड फिलहाल क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था। इस शानदार पारी के साथ सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके नाम अब 680 रन हो गए हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस के बी साई सुदर्शन को पीछे छोड़ा, जिनके खाते में 652 रन हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली 600 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। राजस्थान रायल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंदों पर 50 रन की तेजतर्रार पारी खेली। इस प्रदर्शन के बाद वह इस सीजन 508 रन के साथ तालिका में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी शानदार सीजन खत्म किया। क्लासेन 624 रन के साथ चौथे, ईशान किशन 602 रन के साथ पांचवें और अभिषेक शर्मा 563 रन के साथ आठवें स्थान पर रहे। पर्पल कैप की दौड़ में आर्चर की जोरदार वापसी राजस्थान रायल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी पिछले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर पर्पल कैप की दौड़ को रोमांचक बना दिया है।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 58 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। खास बात यह रही कि उन्होंने हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पावरप्ले के अंदर आउट किया। आर्चर अब इस सीजन 24 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। हालांकि उनसे आगे अभी दो गेंदबाज मौजूद हैं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार और गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा, जिनके नाम 26-26 विकेट हैं।

लैवेंडर तेल और बर्न्स - क्या फायदे हैं?

लैवेंडर तेल के उपयोग करने का मुख्य लाभ, प्राकृतिक रूप से त्वचा के जलने का उपचार है। हालांकि बाजार में कई तरह की बर्न क्रीम मिलती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर में हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य और भलाई की परवाह करते हैं तो आवश्यक तेल जैसे लैवेंडर त्वचा के जलने के उपचार के लिए एक बढ़िया घरेलू उपाय हो सकता है।

मोटापा कम करने के लिए मुद्राएं

मोटापा ऐसी समस्या है जो अपने साथ कई तरह की बीमारी लेकर आती है। समय रहते काबू पाना बहुत जरूरी है। मोटापा कम करने में योग बहुत कारगर होता है। योगासनों के जरिए आप आसानी से मोटापा कम कर सकते हैं। मोटापे को दूर करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। इनका अभ्यास नियमित रूप से कम से कम 15 से 45 मिनट तक करेंगे, तभी इनका फायदा मिलेगा।

ये आदतें नष्ट कर देती हैं शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता

आदतें ही होती हैं जो हमारे जीवन, सेहत और चरित्र आदि का निर्माण करती हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक आदर्श जीवनशैली और अच्छी आदतों का पालन करना होता है। जिसमें नियमित व्यायाम व पौष्टिक आहार आदि शामिल होते हैं। इस तरह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर रोगों से दूर रहता है। वहीं हमारी जीवनशैली से जुड़ी खराब आदतें हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन कुछ खराब आदतें ऐसी भी होती हैं, जिनसे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता खतम हो जाती है।

अकसर जाने-अनजाने हमारी कई आदतें हमें कई रोगों की ओर धकेल देती हैं। इन आदतों के चलते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और बीमारियों के बैक्टीरिया और वाइरस शरीर की प्रणाली पर हमला कर आसानी से उसे खराब करने लगते हैं। इसमें से कई आदतों के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाली आदतें

- लगातार देर तक धूप में रहने से इम्यून पावर कमजोर हो सकती है। यूं तो सुबह की ताजी सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है लेकिन बहुत ज्यादा तेज धूप में रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है और त्वचा कैंसर तक की समस्या हो सकती है।
- बहुत ज्यादा तनाव से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। तनाव होने पर शरीर में कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर बढ़ जाता है जिससे इम्यूनिटी तो कमजोर होती ही है, साथ ही पाचन क्रिया भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है।
- साफ-सफाई के प्रति लचर व्यवहार भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नाकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। शरीर का साफ-सफाई पर ध्यान ना देने से हानिकारक कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे कई बीमारियों और इंफेक्शन हो जाते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा शराब का सेवन या धूम्रपान भी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है।
- जाने-अनजाने में ही सही लेकिन खाने की गलत आदतें और बदपरहेजी धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करती हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकती हैं। एक ताजा शोध के अनुसार तो डिब्बाबंद और माइक्रोवेव में बनाए खाद्य को खाने से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से ये दिमाग व पाचन क्रिया को सीधे-सीधे प्रभावित करती है। और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इसलिए समय से सोएं और पूरी नींद लें। नियमित एक्सरसाइज करें और अच्छा भोजन करें। इस तरह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे।

खुशखबरी देने का सही समय है

बारहवां हफ्ता

गर्भावस्था का बारहवां हफ्ता यानी गर्भवती महिला दूसरी तिमाही में प्रवेश करने वाली है। अब गर्भपात का जोखिम न के बराबर है। यदि मां बनने वाली महिला दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी नहीं दी है तो अब उन्हें यह खबर दे सकती हैं। दूसरी तिमाही में प्रवेश करने पर महिलाएं राहत महसूस करती हैं। अब उन्हें जल्द ही मां बनने का अहसास मन ही मन खुशी देता है। इस समय कुछ महिलाओं का बेबी बंप दिखाई देने लगता है, जब्कि कुछ का दिखाई भी नहीं देता। यदि गर्भवर्ती महिला के अंदर कोई शारीरिक बदलाव नहीं हो रहा तो परेशानी होने की काई बात नहीं है। आंतरिक परिवर्तन लगातार जारी हैं।

बच्चे का विकास

दूसरी तिमाही में प्रवेश कर लिया है, अब बच्चे के विकास में तेजी आएगी। मस्तिष्क हार्मोन का उत्पादन शुरू करेगा और तंत्रिका कोशिकाएं भी जल्द बढ़ेंगी। गर्भ में पल रहा शिशु तरल पदार्थ को चूसना और आहार को निगलना शुरू कर देगा। सब कुछ सही रहने पर शिशु की लंबाई और आकार में परिवर्तन होता रहेगा।

बच्चे की मुट्ठी, खोलने और बंद करने की प्रक्रिया भी अब शुरू होने लगती है। समय समय पर बच्चे के होठ और भौंहे सिकुड़ने लगते हैं। आंखें और कान चेहने के अनुपात में विकसित होने शुरू हो जाता हैं। हफ्तों और महीनों का समय बीतने के साथ शिशु की बनावट में और भी बदलाव आने लगता है।

शरीर में परिवर्तन

गर्भावस्था के बारहवें सप्ताह के दौरान बच्चे की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के कारण गर्भाश्य के आकार में भी परिवर्तन दिखाई देगा। अब मां का पेट पहले से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वजन में दो से तीन पाउंड की वृद्धि हो जाएगी। त्वचा के रंग में भी कुछ परिवर्तन होगा। यदि त्वचा पर दाग हैं तो ये गर्भावस्था के दौरान और गहरे हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में पेट के केंद्र से एक गहरे रंग का रेशा दिखाई देना शुरू हो सकता है, यह शिशु के जन्म के बाद गायब भी हो सकता है।

हर महिला के गर्भावस्था के दौरान अलग-अलग लक्षण होते हैं, इसलिए यदि किसी महिला के लक्षण किसी से भिन्न हैं तो चिंता की बात नहीं है। गर्भावस्था के बारहवें सप्ताह में मां बनने वाली महिला के दिल में जलन भी अधिक हो सकती है। इसमें कमी लाने के लिए दिन भर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आहार लें। चिकित्सक से ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी करें, जिनके सेवन से दिल में जलन न हो। यह समय मोलर गर्भावस्था का हो सकता है। इस समय नाल ठीक से विकसित नहीं होती। धब्बे या योनि से खून बहता दिखाई दे सकता है। इस तरह की परेशानी होने पर बिना किसी लापरवाही के चिकित्सक से परामर्श करें। इस तरह की परेशानी गर्भपात का कारण भी बन सकती है।

क्या उम्मीद की जाती है

दूसरी तिमाही में जाने पर गर्भपात का जोखिम काफी कम हो गया है। सुबह को होने वाली परेशानी, थकान और मितली जैसी दिक्कतें भी कम होंगी। पहले से अच्छा महसूस कर रही होगी। आपके हार्मोन बच्चे के विकास के साथ समायोजन कर रहे हैं और सब अच्छी तरह से चल रहा होना चाहिए। त्वचा सूर्य के प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशील बनी महसूस हो सकती है। इस समय त्वचा पर दाग या काले धब्बे बन सकते हैं। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। संतुलित आहार योजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं रखें। जो महिलाएं पहले गर्भवती रह चुकी हैं, उनसे बात करें और उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करें। अपने और बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए समय-समय पर चिकित्सक से मिलते रहें।

सुझाव / सलाह

सफलता पूर्वक पहली तिमाही पूरी कर ली है। अब दूसरी तिमाही की शुरूआत हो चुकी है। पहले के मुकाबले शारीरिक व मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रही हैं। यदि आने वाले दिनों में गर्भवर्ती महिला को यात्रा करने का विचार बन रहा है तो उसके लिए यह समय बेहतर है। सुबह को होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वाली बधाईयां आपकी खुशी को दोगुना कर देंगी। अन्य महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान की बातों को सुनकर उनसे अपने अनुभवों की तुलना न करें। जरूरी नहीं कि हर महिला की गर्भावस्था के दौरान का अनुभव एक जैसा ही हो। यदि इस सबके बाद मन में अगर कोई प्रश्न है तो चिकित्सक से परामर्श करना अच्छा रहेगा।

गर्भावस्था के बारहवें हफ्ते में

- पहली तिमाही के मुकाबले गर्भवर्ती महिला को कम थकान और मितली भी कम आएगी। इस समय कोशिश करें कि तनाव न लें। इससे ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी।
- अब एरोबिक्स एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में लागू कर सकती हैं। इसके लिए यह सही समय है।
- अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज को शामिल करें, इससे मां और गर्भस्थ शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे।

कैंसर से लड़ने में मददगार हैं ये जादुई फूल

कैंसर रोग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कैंसर के तेजी से बढ़ते मामले और जटिल इलाज के चलते लोगों के लिए यह रोग काफी डरावना बन चुका है। इसका बारे में बात करने से भी लोग घबराते हैं। शोध बताते हैं कि कैंसर दुनिया भर में हर साल हज़ारों मौतों का कारण बनता है। यह दरअसल शरीर में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जो ऊतकों को मार देती हैं और अंततः शारीरिक प्रणाली को नष्ट कर देती हैं। कैंसर मानव प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कैंसर के सबसे आम प्रकार में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर व लिम्फोमा आदि शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कुछ प्राकृतिक औषधियों की मदद से भी कैंसर का इलाज किया जा सकता है। चलिए इस विषय के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि माना जाता है कि डेंडलाइन का फूल कैंसर के उपचार में मददगार होता है।

कैंसर का इलाज: हालांकि कैंसर के कई प्रकारों का इलाज करना संभव होता है, लेकिन इस बीमारी के दोबारा होने का भी बड़ा जोखिम रहता है, जिसके चलते ये बीमारी और भी घातक हो जाती है। इस रोग के साथ इलाज के स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य संगठनों और अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कैंसर के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के प्रयास में हर साल लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहे हैं। हालांकि कैंसर के इलाज के लिये दवाएं, कीमो थेरेपी तथा जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आदि कि मदद से कैंसर के उपचार और बचाव को प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैंसर के उपचार और रोकथाम के लिए प्राकृतिक नुस्खों की मदद भी ली जा सकती है। डेंडलाइन का फूल जिसे कामफूल के नाम से भी जाना जाता है, के फूल के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इसमें कैंसर से लड़ सकने वाले असाधारण औषधीय गुण होते हैं।

कैंसर से लड़ने की क्षमता: डेंडलाइन का फूल, खासतौर पर इसकी जड़ में असंख्य विटामिन और खनिज होते हैं, जोकि मानव प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। डेंडलाइन का फूल विटामिन डी, सी और बी, आयरन, सिलिकॉन, जिंक व पोटेशियम आदि पोषक तत्वों का शरीर में संचार करता है। इन सबके मनुष्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह फूल कोशिकाओं को पोषण देता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके साथ - साथ डेंडलाइन कब्ज, गुर्दे और यकृत रोग, पीलिया, वायरल फ्लू, आदि को भी दूर कर सकता है। यह फूल नई बनी मां के दूध का उत्पादन भी कुशलता से बढ़ा सकता है। डेंडलाइन के फूल को एक उत्कृष्ट रक्त शोधक भी माना जाता है, जो कि चयापचय दर को ठीक बनाए रखने और रक्त विकारों को रोकने में मदद करता है। इस सभी स्वास्थ्य लाभों के साथ डेंडलाइन में कैंसर से लजडने की काबिलियत बी होती है।

विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि डेंडलाइन की जड़ में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकने वाले गुण होते हैं।

जानें पोकवीड केब हर्ब्स के गुणों के बारे में

पोकवीड एक बारहमासी जड़ीबूटी है, जो पूर्वी उत्तर अमेरिका का मूल निवासी है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। इसके बेरीज् और सूखी जड़ों का इस्तेमाल हर्बल उपचार में किया जाता है। पोकवीड सप्लीमेंट अर्क, टिंचर, पाउडर और पुलटिस के रूप में उपलब्ध है। पोकवीड के लिए कोई मानक खुराक निश्चित नहीं हैं।

पोकवीड के गुण

पोक एंटीबायोटिक, एंटी-इंफ्लेमेंटरी, एंटी-रूमेटिक, एंटी-स्कर्वीजनक, एंटी-सिफिलिटिक और एंटी-ट्यूमर के रूप में कार्य करता है। इस संयंत्र के कुछ हिस्सों जैसे बेरीज् और जड़ों को हर्बल उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पोकवीड एक तीखी कड़वी जड़ी-बूटी है जो प्रतिरक्षा और लसीका प्रणालियों के कार्य में मददगार होती है।

बीमारियों के लिए पोकवीड

पोकवीड की जड़ का इस्तेमाल दर्दनाक मसल्स, जोड़ों (गठिया) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह नाक, गला, और सीने में सूजन के अलावा टॉसिलाइटिस, कर्कश गले, लसीका ग्रंथियों की सूजन, ब्रेस्ट में दर्द और सूजन किया जाता है। परंपरागत रूप से, हालांकि, पोकवीड जड़ का इस्तेमाल कभी कभार ही करना चाहिए। अमेरिका के मूल निवासी पोकवीड का चिकित्सा के रूप में इसकी जड़ का सबसे आम उपयोग उल्टी को प्रेरित करने के लिए रेचक के रूप में होता है। बेरीज् को भोजन में रंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और वास्तव में अभी भी खाद्य उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसे कच्चा खाया जाता है तो संयंत्र द्वारा उत्पादित एंजाइम जैसे लेक्टिंस लाल रक्त कोशिकाओं आपस में जुड़ जाती है। लेक्टिंस चिपकने वाले प्रोटीन हैं। ऐसे लेक्टिंस जो ब्लड टाइप के साथ मेल नहीं खाते, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। भोजन से आने वाले कई लेक्टिंस हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत असर होता है। अगर ये लेक्टिंस ब्लड ग्रुप के साथ मेल नहीं खाता, तो शरीर में जलन, सूजन हो सकती है। पोकवीड को अवसादरोधी दवाओं, डिसुलफिरम, ओरल गर्भ निरोधकों और प्रजनन की दवाएं ले रहे लोगों को द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा किसी भी जड़ी बूटियों कको लेने से पहले अपने चिकित्सक और फार्मासिस्ट बताओ।

महिलाओं के लिए पोकवीड

पोकवीड महिलाओं की कई विशिष्ट बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रिओसिस, पोकवीड के निर्धारित उपयोग के साथ हटाया जा सकता है। पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट और पेट में दर्द को भी इसके इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। पोकवीड की जड़ में थोड़ी सी मात्रा मे तेल मिलाकर पेट पर हल्के हाथों से रगड़ने से आराम मिलता है। वैकल्पिक रूप से टिंचर की कम खुराक इस्तेमाल की जानी चाहिए। इन्टर्स्टिशल सिस्टाइटिस एक और भड़काऊ बीमारी है जिसे इसी टिंचर से ठीक किया जा सकता है। बवासीर के दर्द को भी इसकी जड़ों के सत्व से ठीक किया जा सकता है।

पोकवीड को इस्तेमाल कैसे करें

परंपरागत रूप से, पोकवीड के लाल पत्तों को लाकर पानी में उबलकर, अच्छे से निचोड़कर निकाल लें। फिर एक बार और उबला लें। ऐसा कम से कम तीन बार करना चाहिए और हर बार पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। इन उबले हुए पत्तों का इस्तेमाल सलाद के रूप में या चाय के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, यंग शूट को शतावरी के विकल्प के रूप में भी खाया जा सकता है। बेरीज् से रेड जूस निकाल कर फिर इसे पकाया जाता है। इस जूस का इस्तेमाल पाइ बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अन्य जूस में जेली बनाने के लिए भी किया जाता है। पोकवीड के किसी भी हिस्से को कच्चा, असंसाधित नहीं खाया जा सकता है।

अर्थराइटिस

पुराने दिनों से, रूमेटाइड अर्थराइटिस से जुड़े दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए टिंचर उपयोगी है। वैकल्पिक रूप से एक या दो सूखी बेरी लेकर उसे पूरा ही खा लें। बहुत कम मात्रा में टिंचर का इस्तेमाल सिर दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूती

पोकवीड में प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोगों के इलाज की क्षमता भी होती है, क्योंकि इसमें एंटी एड्स दवा के गुण और क्षमता होती है। यह प्रचुर मात्रा में टी-कोशिकाओं पर परस्पर प्रभाव डाल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।

श्वसन संक्रमण का इलाज

पोकवीड के काढ़े का सामान्यत गले में दर्द और टॉसिलाइटिस, ग्रसनीशोथ, अपच जैसे श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, यह ग्रंथियों की सूजन और पुराने संक्रमण के इलाज में भी कारगर है।

कैंसर का इलाज

जल्द ही पोकवीड ने कैंसर का इलाज करने की क्षमता हासिल कर लोक्रिपयता प्राप्त कर ली है, विशेष रूप से स्तन और गर्भाशय के कैंसर के लिए। शोधों से पता चला है कि कैंसर की प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यह जड़ी-बूटी बहुत ही फायदेमंद है। पोक की जड़ एंटीटॉक्सिन थेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कुछ प्रकार के ट्यूमर विकास में बाधा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

रेसिपी

बटर गार्लिक फ्राइड राइस

सामग्री

दो कप पके हुए चावल, लहसुन की 6 कलियां बारीक कटी हुई, आधा कप हरा लहसुन बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ी चम्मच फ्रेंच बींस बारीक कटी हुई, आधा कप पत्तागोभी बारीक कटी हुई, आधा कप फूलगोभी बारीक कटी हुई, एक गाजर छीलकर कद्दूकस कर लें, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, दो बड़े चम्मच मक्खन, स्वादानुसार नमक

विधि

गैस पर नॉन स्टिक पैन में मक्खन गर्म करें। इसमें लहसुन और प्याज डालकर मध्यम आंच पर एक मिनट तक फ्राई करें। अब पैन में फ्रेंच बींस, फूलगोभी, पत्तागोभी, गाजर और नमक डालकर मिक्स करें। अब पके चावल, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा पानी छिड़ककर इन्हें मिलाएं। अब हरा लहसुन डालकर इसे मिक्स करें। फिर पैन को ढक दें और धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं। गैस को बंद करे 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन खोलकर चावल को अच्छी तरह चलाएं। तैयार है बटर गार्लिक फ्राइड राइस। इन्हें प्लेट में निकालकर गर्मागर्म सर्व करें।

चिल्ली पनीर

सामग्री

पनीर - 300 ग्राम, ग्रीन कैप्सीकम - 1 (कटी हुई), रैड कैप्सीकम - 1 (कटी हुई), कार्न फ्लोर - 3-4 स्पून, टमाटो सास - 1/4 कप, तेल- 3-4 चम्मच, सिरका-2 छोटी चम्मच, सोया सास- 2 छोटी चम्मच, चिल्ली सास- 2 छोटी चम्मच, हरी मिर्च - 2-3 (छोटी काटी हुई), अदरक - 1 इंच टुकड़ा (कद्दूकस), नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर- 1/4 छोटी चम्मच, चिल्ली फ्लेक्स -1/4 छोटी चम्मच, अजीनो मोटो-2 पिंच, पोदीना के पत्ते- 12

विधि

पनीर क्यूब्स को एक बाउल में रखें, उसमें डालें नमक, अदरक-लसहुन पेस्ट, मैदा, 1 छोटा चम्मच टोमाटो चिल्ली सॉस और अच्छे से मिलाएं। हरे प्याज को मोटा-मोटा काटें। एक नॉन स्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। लाल मिर्चों के छोटे टुकड़े करके उनके बीज निकालें और पैन में डालें। फिर हरे प्याज डालकर भूने। पैन में शिमला मिर्चें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नमक डालकर कुछ देर पकाएं। 1 बड़ा चममच टोमाटो चिल्ली सॉस डालें और 2 मिनिट तक पकने दें फिर आंच बुझा दें। पनीर के क्यूब्स को पैन में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गारमागरम परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**